● वर्ष-5

● अंक-202

रायपुर, शुक्रवार
10 अप्रैल 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8› फार्मेसी शिक्षा और शोध से...

महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी

संसद में विधेयक के इसी महीने पारित होने की संभावना

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा, और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रभावी होगा।प्रस्ताव के मुताबिक आरक्षण 'वर्टिकल' आधार पर लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए हिस्सा तय किया जाएगा।इस



बिल को लेकर पीएम मोदी ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महिला रिजर्वेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलाव सिर्फ एक कानूनी काम नहीं, बल्कि यह पूरे भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है।उन्होंने सभी सांसदों से इस कदम का साथ देने के लिए एक साथ आने की अपील की और कहा- संसद, सभी दलों से ऊपर उठकर, भारत की महिलाओं के लिए इस महत्वपूर्ण कदम के समर्थन में एकजुट हो। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके।यह एक ऐसा पल है जिसे अब और नहीं टाला जा सकता।

महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने में हर देरी, असल में, हमारे लोकतंत्र की क्वालिटी और सबको साथ लेकर चलने को मजबूत करने में देरी है।अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं, जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। भारत ने हमेशा दिखाया है जब राष्ट्रीय महत्व की बात आती है, तो वह मतभेदों से ऊपर उठकर एकता के साथ काम कर सकता है। यह भी ऐसा ही एक क्षण है।राज्यों की विधानसभाओं में भी इसी अनुपात में सीटों का आरक्षण होगा। सरकार एक संशोधन बिल के एक संविधान साथ-साथ परिसीमन कानून में संशोधन के लिए अलग साधारण बिल भी लाएगी। ताकि नए सिरे से सीटों का निर्धारण हो सके। नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। यह कानून राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा।

तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव

80% से अधिक मतदान

नईदिल्ली। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2026 विधानसभा चुनावों के लिए गुरुवार को मतदान खत्म हो गया है। शाम तक मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शाम 5 बजे तक असम में 84.42%, केरल में 75.01% और पुडुचेरी में 86.92% मतदान हुआ। असम में, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जलुकबारी स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान किया। वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा और उनके बच्चे भी थे। इससे पहले, उन्होंने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की।

जलुकबारी लगभग 25 वर्षों से सरमा का गढ़ रहा है। वे 2001 से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब उन्होंने असम गण परिषद के नेता भृगु कुमार फुकन को हराया था। इस बीच, चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में सामान्य मतदान दर्ज



किया गया। शाम 5 बजे तक, कर्नाटक के बागलकोट में 65.68%, दावनगेरे दक्षिण में 63.04%, नागालैंड के कोरिडांग में 80.62% और त्रिपुरा के धर्मनगर में 79.84% मतदान हुआ।

इससे पहले असम में तीन चरणों में कराए गए 2021 के विधानसभा चुनावों में लगभग 82 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इस बार एक चरण के चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। अधिकारियों ने बताया कि अपराह्न तीन बजे तक कामरूप के चमारिया में सबसे अधिक 84.43 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि न्यू गुवाहाटी में सबसे कम 60.57% मतदान हुआ।

लुकबाड़ी सीट से दोबारा चुनाव मैदान में उतरे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कामरूप (मेट्रो) जिले के गराल बुनियादी एलपी स्कूल में अपनी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा, बेटे नंदिल और बेटी सुकन्या के साथ मतदान किया। मतदान से पहले उन्होंने परिवार सहित नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर और उत्तर गुवाहाटी के डौल गोविंदा मंदिर में पूजा-अर्चना की। उधर, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपनी मां डॉली गोगोई के साथ जोरहाट के डीसीबी एलपी स्कूल में वोट डाला।

अब तक वोट डालने वाले अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में नाजिरा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, जोरहाट में केंद्रीय मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, खोवांग में असम गण परिषद अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई और शिवसागर में रायजोर दल प्रमुख अखिल गोगोई शामिल हैं। केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा , मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के शासन और कल्याणकारी मॉडल के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने के प्रयास में है।



रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल की चाची स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल जी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का आधार गलत: केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केरल के सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन किया। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला इस धारणा पर आधारित है कि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं निम्न हैं। इसी वजह से सभी महिलाओं को एंट्री देने का आदेश दिया गया।सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों की बुधवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई कर रही है। इसमें विभिन्न धर्मों में प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रता की



सीमा और दायरे पर भी विचार किया जा रहा है।केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्होंने लिखित स्टेटमेंट में ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। केरल के कोट्टनकुलंगरा श्री देवी मंदिर में, चामयाविलक्कु उत्सव के दौरान पुरुष हर साल महिलाओं के वेश में सजते हैं, जो देवी के सम्मान में सदियों पुरानी परंपरा है। वे ब्यूटी पार्लर जाते हैं और परिवार की महिलाएं उन्हें साड़ी पहनने में मदद करती हैं। मेहता ने कहा कि इसलिए यह पुरुष केंद्रित या महिला केंद्रित धार्मिक मान्यताओं का सवाल नहीं है। वर्तमान मामले में यह महिला केंद्रित है।एक उदाहरण देता हूं, कई मंदिरों में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद या अंतरात्मा की आवाज पर कहता है कि वह मांसाहारी भोजन करना चाहता है, तो वह किसी खास संप्रदाय के पास जाकर यह नहीं कह सकता कि मेरा यह अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन

धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं। 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं।सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटीशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे।

प्रमुख समाचार

अमेरिका और ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता

नईदिल्ली। पश्चिम एशिया में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जारी हिंसक संघर्ष ने आज एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति जताई है, जिसमें दोनों पक्षों ने लड़ाई रोकने और होर्मुज को खुला रखने का वादा किया है। ऐसे में अब बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। इसके लिए



अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष टीम भेजी जा रही है। इस टीम का नेतृत्व खुद जेडी वेंस करेंगे।हालांकि लेबनान को लेकर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। इस्राइली सेना इस्राइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों और नेटवर्क को निशाना बनाया है। आईडीएफ के अनुसार, अली यूसुफ हर्शी, जो हिजबुल्ला के महासचिव नईम कासिम के निजी सचिव और करीबी सलाहकार थे, संगठन के संचालन में अहम भूमिका निभाते थे।सेना का कहना है कि हर्शी कासिम के कार्यालय के प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े प्रमुख काम संभालते थे, जिससे उनकी संगठन में महत्वपूर्ण स्थिति थी।

सरकार में आए तो जवानों को मिलेगा 'पूरा हक': राहुल

नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शौर्य दिवस के अवसर पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो मौजूद भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करेगी और जवानों



को उनका पूरा अधिकार दिलाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में राहुल गांधी ने सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर जवानों की वीरता और बलिदान को सलाम किया। उन्होंने लिखा कि सीएपीएफ के जवान देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे सीमाओं की रक्षा हो, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुकाबला या फिर चुनाव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। अपनी पोस्ट में सीएपीएफ के भीतर प्रमोशन और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। वर्षों की सेवा और समर्पण के बावजूद जवानों को समय पर पदोन्नति नहीं मिलती और उन्हें अपने ही बलों में शीर्ष नेतृत्व के अवसर से वंचित रखा जाता है।

संत रामपाल को राहत देशद्रोह में जमानत

नईदिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को देशद्रोह के मामले में जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले का रामपाल के अनुयायियों ने स्वागत किया।

क्योंकि वो लंबे वक्त से उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। दरअसल, ये मामला साल 2014 के उस



विवादास्पद घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है जब अदालत द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना के मामले में पेश न होने के कारण पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आश्रम की घेराबंदी की थी। इस दौरान पुलिस और रामपाल के अनुयायियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने देशभर का ध्यान खींचा था। अंतत: पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही थी, जिसके बाद से वो जेल में ही हैं। इस मामले में रामपाल को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी और वो लगभग 11 साल, 4 महीने और 20 दिन से जेल में बंद हैं। फिलहाल वो हिसार केंद्रीय जेल में है। उनके वकीलों ने लंबे समय से जेल में रहने और मामले के तथ्यों को आधार बनाकर जमानत की अपील की थी।

लश्कर-हिजबुल से जुड़े दो सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

नईदिल्ली। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को आतंकी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से जुड़े दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। आजतक के सूत्रों के जरिए यह जानकारी मिली है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ब) के तहत सरकारी मशीनरी में पैठे



आतंकी तत्वों को बाहर निकालने के अभियान के तहत की गई है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में रामबन के शिक्षा विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फरहत अली खांडे और बांदीपोरा के ग्रामीण विकास विभाग का मोहम्मद शफी डार शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन पर आतंकी नेटवर्क चलाने, फंड जुटाने और सुरक्षा बलों की जानकारी साझा करने के गंभीर सबूत पाए हैं। एलजी ने आतंकवाद के इस खतरे को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई है। अब तक इस कैंपेन के तहत 90 से ज्यादा कर्मचारी सेवा से बाहर किए जा चुके हैं। रामबन में शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फरहत अली खांडे की असलियत साल 2011 में सामने आई थी।

यूपी में बारिश से तबाही पर मुआवजे का ऐलान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में एक हाई लेवल बैठक कर प्रदेश में बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान की समीक्षा की। पिछले एक हफ्ते में प्राकृतिक आपदा के कारण यूपी में 20 लोगों की जान गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए और 33 पशुओं की हानि हुई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व



और कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि हर प्रभावित किसान और बटाईदार के नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और राहत वितरण में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनहानि, पशु हानि और घायलों के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। राहत आयुक्त कार्यालय से सभी जिलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि राहत कार्यों में लापरवाही अक्षम्य होगी और जवाबदेही तय की जाएगी।

महिला आरक्षण से कानून-निर्माण में भागीदारी-लोकतंत्र का शुभसंदेश

ब्रजमोहन श्रीवास्तव

स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में महिलाओं ने समाज, परिवार, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेना, प्रशासन, चिकित्सा, कानून, शिक्षा, व्यवसाय और शोध सहित अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है लेकिन राष्ट्रीय क़ानून निर्माण में उनकी भागीदारी नगण्य रही है। वे मतदाता थीं, कार्यकर्ता थीं, समाज की धुरी थीं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में अवसर तो मिले, परंतु उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं था। दशकों तक कानून-निर्माण के मंच पर उनकी उपस्थिति राजनैतिक परिस्थितियों और दलों की प्राथमिकताओं व नेताओं की मेहरबानी पर निर्भर रही।

तीन दशकों से अधिक समय के लंबे इंतजार के बाद अब यह स्थिति निर्णायक रूप से बदलने जा रही है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया बल्कि महिलाओं द्वारा परिणाम की चिंता किये वगैर निरंतर प्रयासों और हर क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका की छाप छोड़ने का परिणाम है। महिला आरक्षण संविधान-106वां संशोधन अधिनियम, 2023 के पारित होने के साथ भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं का नेतृत्व अब केवल सहायक भूमिका तक सीमित नहीं

रहेगा, बल्कि वे राष्ट्र के नीति-निर्माण व क़ानून बनाने में बराबरी से भागीदार होंगी ।

यह ऐतिहासिक निर्णय एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। श्री मोदीजी का मानना है कि आरक्षण देने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है इसलिए इसे अब और नहीं टाल सकते । हालांकि, इस संशोधन का क्रियान्वयन आगामी जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है इसलिए यह 2029 के आम चुनावों में भी लागू हो सकता है।

महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों की यात्रा के यहाँ तक पहुँचने में लगभग तीस वर्ष लगे है। 1992-93 में 73वें



और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगरीय निकायों में 33ब आरक्षण लागू किया गया, जिससे महिलाओं की भागीदारी का मार्ग कानूनी रूप से प्रशस्त हुआ। इसके बाद कई राज्यों ने इसे 50ब तक बढ़ाया। आज देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों में 50ब महिला आरक्षण लागू है फलस्वरूप आज महिलाएँ अध्यक्ष, महापौर तथा पार्षद या नगर सेवक के लगभग एक लाख पदों पर प्रभावी नेतृत्व दे रही हैं।पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ने प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और विकास को नई दिशा दी है। वर्तमान में लगभग साढ़े चौदह लाख से अधिक महिलाएँ ग्रामीण शासन में जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच व पंच के निर्वाचित पदों पर कार्यरत हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ उत्कृष्ट नेतृत्व दे सकती हैं।कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी क्षमता सिद्ध की है। सेबी द्वारा 2013 में बनाए गए नियमों के तहत 2015 से सभी सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य की गई। आज देश की 1000 शीर्ष कंपनियों में महिला नेतृत्व एक अनिवार्य और प्रभावी घटक बन चुका है।यह स्पष्ट है कि पिछले 30 वर्षों में महिलाओं का नेतृत्व क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। इसी क्रमिक मजबूत आधार के कारण 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित करना पड़ा, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33ब महिला आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है । यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने का संकल्प है जिससे कुल आबादी का 50 प्रतिशत जो अभी तक मतदान तक सीमित था आने वाले समय में क़ानून निर्माता की श्रेणी में आ जाएगा।

दुर्भाग्यवश, आज भी कुछ राजनीतिक दल और विपक्षी नेता इस ऐतिहासिक निर्णय को संदेह की दृष्टि से देखते हुए भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना किसी राजनैतिक लाभ का विषय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का नैतिक दायित्व है जिसे पूरा करने के लिये एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ रही है।

कांग्रेस नेता के ढाबे में बिक रही अवैध शराब, आरोपी हिरसात में



बलौदाबाजार। कसडोल ब्लॉक के ग्राम कटगी में उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई, जब अवैध शराब बिक्री की शिकायत से बौखलाए ढाबा संचालक ने एक ग्रामीण के साथ मारपीट की। इसकी सूचना मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हुए और ढाबा संचालक कसडोल ब्लॉक ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत थवाईत और उसके बेटे संतोष थवाईत की जमकर धुनाई की। वहीं बवाल की सूचना पर बलौदाबाजार से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कटगी पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता-पुत्र को हिरासत में लिया है।

बता दें कि ग्रामीणों ने ग्राम कटगी में संचालित ढाबे में अवैध शराब बिक्री की शिकायत कलेक्टर एवं एसपी से की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कार्रवाई नहीं होने पर ढाबा संचालक के हौसले बढ़ गए और उसने ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

साथ ही बाहर से गुंडे बुलाकर उन्हें धमकाने की कोशिश की, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और फिर जमकर हंगामा मचाया। घटना की सूचना मिलते ही कसडोल थाना पुलिस और बलौदाबाजार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस की मौजूदगी के बाद स्थिति शांत बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी पिता-पुत्र को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि जिले में अवैध शराब के साथ अवैध मादक पदार्थों की जमकर बिक्री हो रही है। पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई कर वाहवाही लूटने में लगी है। ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही है। कसडोल पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम कटगी की घटना में यह बात सामने आई है कि पहले ग्रामीणों ने कसडोल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कलेक्टर व एसपी से शिकायत की गई थी। इससे बौखलाए ढाबा संचालक ने ग्रामीणों के साथ मारपीट व गाली-गलौज की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। बलौदाबाजार में कार का शीशा टूटने की रिपोर्ट पर भी पुलिस ने तत्काल गंभीरता नहीं दिखाई थी। एक साथ चार गाड़ियों के शीशे टूटे थे और बैटरियों की चोरी हुई थी। इसके बाद मोहल्ले के युवाओं ने ही एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। वहीं अभी भी पुलिस बाकी कार की बैटरियों की पता नहीं लगा पाई है, जबकि बलौदाबाजार में पूर्व में भी वाहनों के बैटरी चोरी का मामला आ चुका है।

सीएम के पहले ही युकां जिलाध्यक्ष ने कर दिया चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण



अंबिकापुर। जिले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दौरे से ठीक पहले सियासी माहौल गरमा गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के आधिकारिक अनावरण से पहले ही युवा कांग्रेस सरगुजा जिला अध्यक्ष विकल झा के साथ कार्यकर्ताओं ने देर रात नारियल फोड़कर और माल्यार्पण कर प्रतीकात्मक अनावरण कर दिया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन भाजपा नेता रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा के लिए भव्य तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि यह शहीद का अपमान है, और प्रतिमा स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई।

गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दोनों प्रतिमाओं का विधिवत अनावरण करेंगे, लेकिन उससे पहले हुए इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक तैयारियों और सियासत पर कई सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी द्वारा स्वयं घटना को अंजाम दिए जाने पार्टी की शैली पर सवाल खड़े करता है।

सट्टा केस में महापौर का भतीजा पकड़ाया, लेकिन जेल भेजने से पहले बिगड़ी तबीयत



बिलासपुर। आईपीएल सट्टे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद जूना बिलासपुर से गिरफ्तार आरोपियों में से एक को जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरे आरोपी महापौर का भतीजा और भाजपा नेता विशाल विधानी जेल जाने के डर से अचानक बीमार पड़ गया। जिसका सिम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक जेल जाने से बचाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उसे वीआइपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। वहीं परिजन दिनभर उससे मिलने पहुंचते रहते हैं। दरअसल, बीते 5 अप्रैल को पुलिस ने जूना बिलासपुर में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए दीपक भक्तानी और विशाल विधानी को रंगे हाथों पकड़ा था। इनके पास से 1.10 लाख रुपये नगद, मोबाइल और स्कूटी जब्त किया गया था। पुलिस को पता चला था कि दीपक को विशाल विधानी सट्टे का लिंक उपलब्ध कराता था। दोनों के तार गोवा के राजा आहूजा से जुड़े हुए हैं। इधर, शहर में प्रभावशाली लोगों की पकड़ पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट से जेल वारंट जारी होने के बाद आरोपी विशाल विधानी को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक, जेल में दाखिले की कागजी कार्रवाई जारी थी।

इसी दौरान आरोपी विशाल विधानी ने अचानक तबीयत बिगड़ने का हवाला देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। आनन-फानन में जेल डॉक्टर को बुलाया गया। लेकिन जेल में उपयुक्त सुविधा न होने के कारण बिना ज्यादा देर किए उसे सिम्स रेफर कर दिया गया। यहीं से कथित तौर पर रसूख का खेल शुरू हुआ। पुलिस तुरंत विशाल विधानी को सिम्स अस्पताल लेकर पहुंची और भर्ती करा दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद जेल आरआई या जेल विभाग को इस पूरे घटनाक्रम की कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। यह लापरवाही या फिर मिलीभगत—दोनों ही स्थिति में गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आरोपी को भी इतनी तेजी से राहत मिलती है, या फिर यह सब कुछ सिर्फ रसूख और पहुंच के दम पर हुआ? जेल जाने से ठीक पहले अचानक तबीयत बिगड़ना और फिर सीधे बड़े अस्पताल में एडमिट होना। यह पूरा मामला संदेह के घेरे में है। अब सवाल यह है कि आरोपी विशाल विधानी के इस 'बीमारी ड्रामे' की निष्पक्ष जांच होगी या मामला रसूख के नीचे दबा दिया जाएगा।

रेत परिवहन के नाम पर अवैध वसूली करने वालो पर होगा एफआईआर



अभनपुर। अवैध वसूली के संगठित खेल पर प्रशासन ने आखिरकार शिकंजा कसा है। ग्राम दुलना में रेत परिवहन के नाम पर चल रहे वसूली रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद तहसीलदार ने सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को हुई जांच में खुलासा हुआ कि रेत से भरे वाहनों से बाकायदा डायरी बनाकर पैसे वसूले जा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह पूरा खेल गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो खुद को ग्राम विकास समिति से जोड़कर वसूली कर रहे थे।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर ने जांच कर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ तौर पर अवैध वसूली की पुष्टि हुई। इसके बाद तहसीलदार ने थाना प्रभारी गोबरा नवापारा को कड़ा पत्र जारी करते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में ग्राम विकास समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित कई लोग शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस इस संगठित वसूली गिरोह पर तुरंत कार्रवाई कर पाएगी या मामला फिर ठंडे बस्ते में जाएगा? फिलहाल प्रशासन के इस कड़े रुख से अवैध वसूली में लिप्त लोगों के बीच डर और बेचैनी साफ नजर आ रही है।

बारिश से पहले एनएच 343 को चलने योग्य बनाने के निर्देश

■ **बारिश से पहले एनएच 343 को चलने योग्य बनाने के निर्देश, एसई ने लगाई फटकार**



सरगुजा। अपने दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे सीई ने निर्माण कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही कंसल्टेंट कंपनी के अथॉरिटी इंजीनियर को स्पष्ट निर्देश दिए है कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले गिट्टी वाला काम पूर्ण कर लिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना ना करना पड़े। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप सरगुजा के दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 130 और 43 का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्य रूप से उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के कार्यों की जानकारी ली। सीई ने एनएच ईई आरडी ताम्ब्रे के साथ रजपुरी खुर्द से पस्ता पाढ़ी और बलरामपुर से रामानुजगंज के चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान यह जानकारी आई कि रजपुरी खुर्द से पाढ़ी के बीच अर्थ वर्क, पाइप पुलिया, बॉक्स कलवट के काम होने है। इसके साथ ही रामानुजगंज के बीच जीएसबी का काम चल रहा है और कुछ स्थानों पर ट्रायल के लिए डामरीकरण भी कराया जा रहा है। सीई ने निर्माण एजेंसी के प्लांट का निरीक्षण किया। एनएच ईई आरडी ताम्ब्रे ने बताया कि एनएच पर वर्तमान में 10-12 प्रतिशत काम हुआ है और बारिश तक गिट्टी वाला काम करना है। ऐसे में सीई ने बारिश से पहले सब ग्रेस का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि बारिश के समय लोगों को आवगमन में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि एनएच 343 पर रजपुरी खुर्द से पाढ़ी के बीच 49 किलोमीटर सड़क के लिए 397.44 करोड़, बड़की महरी से रामानुजगंज के बीच 29.430 किलोमीटर सड़क के लिए 199.05 करोड़ व संजय नगर से राजपुरीखुर्द के बीच 13.1700 किलोमीटर बाईपास सड़क निर्माण के लिए 149.94 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बताया जा रहा है कि एनएच के सीई कश्यप ने कंपनी के प्लांट के साथ ही अर्थ वर्क में कम्पैक्शन, सब ग्रेड की ग्रेडिंग की जांच की। इस दौरान उन्होंने ठेकेदर और कंसल्टेंट एजेंसी के अथॉरिटी इंजीनियर को फटकार लगाते हुए स्पष्ट दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सड़क का निर्माण तय किए गए मानकों के अनुरूप किया जाए। वहीं उन्होंने सड़क में सुरक्षा मानकों का भी पालन करने के निर्देश दिए। ठेकेदार द्वारा जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े पेड़ों के डंगाल गिराकर छोड़ दिया गया ताकि लोग उस लेन में आवागमन नहीं कर पाए। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सीई ने ठेकेदार को संकेतक लगाने और सुरक्षा मानकों का ख्याल रखने के निर्देश दिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर अभी से सवाल उठ रहे है। सड़क निर्माण की गति काफी धीमी है ऐसे में इस बार बारिश के समय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

पटवारी की गलती से भड़का जमीन विवाद, कोर्ट का आदेश भी बेअसर

डोंगरगढ़। ग्राम पारागांव खुर्द में जमीन के सीमांकन में हुई गड़बड़ी ने दो परिवारों के बीच गंभीर विवाद खड़ा कर दिया है। राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण शुरू हुआ यह मामला अब इतना बढ़ चुका है कि गांव में कभी भी बड़े संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। लिखन लाल लोधी और रामकुमार लोधी के बीच जमीन को लेकर चल रहा विवाद आए दिन गाली-गलौज और झगड़े में बदल रहा है, जिससे पूरे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

बताया जा रहा है कि लिखन लाल लोधी ने वर्ष 2008 में करीब 1.42 एकड़ जमीन खरीदी थी और तब से उस पर कब्जे में है। उसी समय रामकुमार लोधी ने भी पास की जमीन खरीदी थी। विवाद तब शुरू हुआ जब खसरा नंबर 217/3 और 217/5 के सीमांकन और नक्शों में अंतर सामने आया। आरोप है कि राजस्व अमले द्वारा नक्शे में की गई काट-छांट के कारण जमीन की स्थिति बदल गई, जिससे दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

लिखन लाल का कहना है कि वे वर्षों से न्याय के लिए तहसील से लेकर आयुक्त और राजस्व मंडल तक भटक रहे हैं और कई जगह से उनके पक्ष में आदेश भी मिले हैं। इसके बावजूद उन्हें जमीन पर न्याय नहीं मिल पाया। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) डोंगरगढ़ ने भी अपने आदेश में विवादित जमीन पर लिखन लाल का कब्जा माना और दूसरे पक्ष को हस्तक्षेप से रोका था। साथ ही फसल लौटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन आदेशों का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा। आरोप है कि हर साल उनकी फसल जबरन काट ली जाती है और विरोध करने पर धमकी दी जाती है। मामला जब उच्च स्तर पर पहुंचा तो आयुक्त दुर्ग संभाग और राजस्व मंडल ने भी माना कि निचले स्तर पर गलती हुई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बेलबहरा की विवादित भूमि पर खरीदी-बिक्री व अन्य पर रोक

एमसीबी। कलेक्टर जनदर्शन में आई शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां ग्राम बेलबहरा की एक विवादित भूमि पर सभी प्रकार के लेन-देन और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम बेलबहरा तहसील मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नंबर 62 जिसका पुराना खसरा नंबर 32 जो वर्ष 1944-45 के राजस्व रिकॉर्ड में "छोटे झाड़ का जंगल" के रूप में दर्ज थी। आरोप है कि वर्ष 1980-81 में बिना किसी वैधानिक आदेश के इसे रामसुभग के नाम दर्ज कर दिया गया। इसके बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं को भूमि आबंटित होना बताकर शासकीय अनुमति प्राप्त की गई और भूमि का विक्रिय भी कर दिया गया। इस पूरे मामले को शिकायत के माध्यम से कलेक्टर जनदर्शन में उठाया गया। इस भूमि की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़ को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं जांच में सामने आया कि भूमि विक्रय की अनुमति लेते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई।

कोंडागांव में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर

कोंडागांव। जिला प्रशासन कोंडागांव के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए तीन दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना तथा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर वितरण करना था। शिविर के अंतिम दिन को नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल की उपस्थिति में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा 4 दिव्यांगजनों को कैलीपर्स, 14 लोगों को कृत्रिम हाथ-पैर, 11 हितग्राहियों को ट्रायसायकल तथा 3 लोगों को व्हीलचेयर प्रदान की गई। इसके साथ ही कुल 55 पंजीकृत दिव्यांगजनों में से 46 का नि:शक्त प्रमाण पत्र बनाकर मौके पर ही वितरण किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को कानूनी सहायता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री जसकेतु उसेंडी, समाज कल्याण विभाग की अधिकारी व अन्य की उपस्थिति रही।

जिले में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक अभियान

मोहला। आकांक्षी जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलेभर में विविध कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग आईसीडीएस ने समन्वय के साथ सक्रिय भूमिका रही। कुटुंब अभियान के अंतर्गत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं व बच्चों को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई। साथ ही सास-बहू सम्मेलनों का आयोजन कर परिवार स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़े विषयों पर संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीकाकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, छोटे बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण की आवश्यकता को समझाया गया।

अम्बिकापुर में निर्धारित कार्यक्रम से पहले प्रतिमा अनावरण

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का निर्धारित कार्यक्रम से पहले अनावरण किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा ने अपने साथियों के साथ देर रात प्रतिमा का अनावरण कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मामले में महापौर मंजूषा भगत ने पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा रविवार देर रात करीब 12 बजे आकाशवाणी चौक पहुंचे और आधिकारिक कार्यक्रम से पहले ढंकी हुई प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़ा, अगरबत्ती जलाई, प्रतिमा से कवर हटाकर माल्यार्पण किया और नारेबाजी की। विकल झा ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता स्वर्गीय रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमा स्थल पर भव्य सजावट की गई, जबकि शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल की अनदेखी की गई।

घर से हाथ पकड़कर खींचा और कार में बिठाकर ले गए

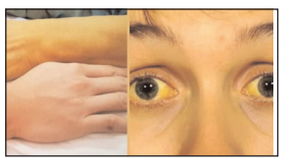
जगदलपुर। कांकेर जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बालिका का अपहरण कर लिया। यह घटना प्यार के चक्कर में जबरन शादी करने के इरादे से अंजाम दी गई थी। बालिका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर बालिका को मुक्त कराया। अंतागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि सात अप्रैल को अपहृता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि रंजन मिश्रा ने अपने दो साथियों के साथ उनकी पुत्री को जबरदस्ती शादी करने के लिए घर से खींचकर गाड़ी में बिठाया। इन साथियों में प्रियांशु गुड्डू कुमार उपाध्याय (21 वर्ष) और लाली टेकाम (31 वर्ष) शामिल थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों का पता लगाया और घेराबंदी कर उन्हें केवटी भानुप्रतापपुर के पास से पकड़ा। पूछताछ में आरोपी रंजन मिश्रा ने बताया कि बालिका कुछ महीने पहले हैदराबाद में काम करती थी।

चिरमिरी में पीडीएस चावल की कालाबाजारी गोदाम सील

एमसीबी। चिरमिरी क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी चावल के भंडारण के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। प्रशासन को शिकायत मिली कि एकता नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी गोदाम में सरकारी राशन का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल एक संयुक्त टीम का गठन किया। इस टीम में खाद्य विभाग के निरीक्षक एवं स्थानीय पुलिस बल के जवान शामिल थे। निर्धारित योजना के तहत टीम ने गोदाम पर दबिश दी। मौके पर पहुंचकर गोदाम का ताला खुलवाया गया और जब तलाशी ली गई तो अंदर से करीब 15 क्विंटल पीडीएस चावल बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह चावल सरकारी वितरण प्रणाली का पाया गया, जिसे अवैध रूप से संग्रहित किया गया था। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पूरे चावल को जब्त कर लिया और संबंधित गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि चिरमिरी क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। भविष्य में भी जहां कहीं इस तरह की अनियमितता या अवैध भंडारण की शिकायत मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भिलाई में 22 बच्चों में दिख पीलिया के लक्षण

■ **वार्ड क्रमांक 67 के 22 बच्चों में पीलिया के लक्षण मिले,इनमें से 2 आईसीयू में है.**



भिलाई। भिलाई के सेक्टर 7 वार्ड क्रमांक 67 में पीलिया का प्रकोप सामने आया है।यहां पर एक के बाद 22 बच्चों में पीलिया की शिकायत सामने आई। जिसमें से 2 बच्चों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। आपको बता दें कि वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू नगर निगम की टीम लेकर लोगों के घर पहुंचे हैं।

लोगों के घरों से पानी का सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। इससे पहले जिले के नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में गंदा पानी पीने से पीलिया फैलने का मामला सामने आया था। एक महीने से क्षेत्र में लगातार पीलिया के मरीज मिल रहे थे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल था।

उतई नगर पंचायत में पीलिया फैलने का कारण नालियों का गंदा पानी और हैंडपंप का दूषित पानी थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह समस्या सिर्फ उनके घर तक है, लेकिन धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगे,जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया। वहीं साल 2025 में दुर्ग शहर के गौतम नगर क्षेत्र में लगातार पीलिया के मरीज मिले थे ।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो 25 लोग संक्रमित हुए थे।

यहां पर भी दूषित जल पीने के कारण पीलिया का संक्रमण लोगों में हुआ था। पांचों तरह के पीलिया के लक्षण एक जैसे होते हैं। शुरुआती दो-तीन दिनों तक लगातार बुखार आना, उसके बाद उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना, पेशाब में पीलापन होना, पेट में खराबी होना, लूज मोशन होना, इसके बाद आंखों में पीलापन होना, बहुत ज्यादा वीकनेस या कमजोरी लगना। इसके साथ ही भूख ना लगना इस तरह के लक्षण पीलिया में देखने को मिलते हैं। पीलिया कम है तो लक्षण कम दिखाई पड़ेंगे। पीलिया गंभीर है तो लक्षण ज्यादा देखने को मिलेंगे।

आपको बता दें कि पीलिया के मरीज गर्मी और बारिश दोनों के सीजन में देखने को मिलते हैं। लेकिन बारिश में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। पीलिया 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए, बी,सी, डी और ई होता है। बारिश के मौसम में दूषित और गंदा पानी से फैलने वाला पीलिया ए और ई किस्म का होता है। गंदे पानी से जो वायरस फैलता है। वह हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई कहलाता है।

बीजापुर से काम की तलाश में निकले 12 लोग गंभीर रूप से घायल

बीजापुर। जिले के भोपालपटनम से लगे महाराष्ट्र के सोमनपल्ली क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। काम की तलाश में पलायन कर रहे मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया।

हादसे में करीब 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, जिले के भोपालपटनम इलाके से मजदूर काम की तलाश में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गुरुवार सुबह सोमनपल्ली के पास पिकअप वाहन चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया, जिससे वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तत्काल भोपालपटनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद कुछ गंभीर रूप से घायल मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए बीजापुर रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का उपचार भोपालपटनम अस्पताल में किया जा रहा है। भोपालपटनम थाना प्रभारी जीवन कुमार जांगड़े ने बताया कि महाराष्ट्र के आसरली थाना क्षेत्र के सोमनपल्ली के पास कल गुरूवार सुबह यह हादसा हुआ।

संक्षिप्त समाचार

850 श्रद्धालुओं का दल रामलला एवं काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु रवाना

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय



भक्ति और उत्साह का अद्भुत वातावरण देखने को मिला, जब कैबिनेट मंत्री श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री टंकराम वर्मा ने 850 तीर्थयात्रियों के दल को विशेष 'रामलला दर्शन' ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। जय श्री राम के जयघोष से पूरा स्टेशन गूंज उठा और श्रद्धालुओं के चेहरों पर पहली बार प्रभु श्रीराम के दर्शन की खुशी साफ झलक रही थी। तीर्थयात्रियों में अयोध्या जाने को लेकर अत्याधिक उत्साह का वातावरण था। अधिकांश श्रद्धालु पहली बार रामलला के दर्शन करने जा रहे थे और उन्होंने इस अवसर के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का आभार व्यक्त किया। पर्यटन मंत्री श्री अग्रवाल ने यात्रियों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और यात्रा के संबंध में चर्चा करते हुए उनकी सुविधाओं का भी जायजा लिया। यह तीर्थयात्रा अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ-साथ काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का भी अवसर प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा आईआरसीटीसी एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के माध्यम से भोजन, आवास, चिकित्सा और भ्रमण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबंध किया गया है। यात्रा के दौरान अधिकारी-कर्मचारी श्रद्धालुओं की सहायता में तत्पर नजर आए और यात्री भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे।

राज्य के सिंचाई जलाशयों में अभी 67 प्रतिशत से अधिक जल भराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 12 वृहद एवं 34



मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में इस वर्ष जल भराव की स्थिति काफी बेहतर है। वर्तमान में राज्य के कुल 46 प्रमुख सिंचाई जलाशयों में औसत रूप से 67.43 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 में इसी अवधि में औसत रूप से 45.23 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 के 42 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह स्थिति राज्य में बेहतर वर्षा, सुनियोजित जल प्रबंधन तथा जलाशयों के प्रभावी संचालन का परिणाम है। राज्य के 12 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 68.19 प्रतिशत जल भराव है, जबकि वर्ष 2025 में यह 45.84 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 में 38.62 प्रतिशत था। प्रमुख वृहद जलाशयों में शामिल मनियारी जलाशय में 90.41 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली में 86.85 प्रतिशत, खारंग में 84.99 प्रतिशत, दुधावा में 84.54 प्रतिशत, रविशंकर सागर में 76.72 प्रतिशत, सोंढूर में 70.65 प्रतिशत एवं तांदुला में 66.19 प्रतिशत में जल उपलब्ध है। वहीं मिनीमाता बांगो जलाशय में 63.86 प्रतिशत तथा केलो में अभी 51.83 प्रतिशत जल भराव है। कोडार जलाशय में अपेक्षाकृत कम 35.45 प्रतिशत जल उपलब्ध है।

सोनपुरी डायवर्सन के कार्यों के लिए 4.04 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड-खैरागढ़ की सोनपुरी डायवर्सन के शीर्ष कार्य एवं नहरों के रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 04 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत रूपांकित सिंचाई क्षमता 115 हेक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 59 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 50 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 165 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

15 अप्रैल को होगी साय मंत्रिपरिषद की बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हैं। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में होगी।

शासकीय फार्म में नील-हरित काई उत्पादन की शुरुआत

रायपुर। रायगढ़ जिले में स्थित शासकीय कृषि प्रक्षेत्र बेहरामार में नील-हरित शैवाल (ब्लू-ग्रीन एल्गी) के उत्पादन प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी है। यह पहल किसानों को किफायती दर पर जैविक उर्वरक उपलब्ध कराने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नील-हरित शैवाल, जिसे वैज्ञानिक रूप से सायनोबैक्टीरिया कहा जाता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है। यह प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके उपयोग से प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की आपूर्ति संभव है, जिससे रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस जैव उर्वरक का उपयोग विशेष रूप से धान की फसलों में लाभकारी है।

छत्तीसगढ़ को ज्ञान, कौशल और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना हमारा ध्येय : साय

रायपुर से शुरू होगा ' एआई सक्षम शिक्षा अभियान', 2 लाख से अधिक शिक्षकों को मिलेगा एआई प्रशिक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख श्री संजय जैन एवं गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख श्री राकेश रंजन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान करते हुए उन्हें शॉल एवं बस्तर कला की प्रतिकृति भेंट की। ।

गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख श्री संजय जैन ने रायपुर जिला प्रशासन और गूगल के मध्य हुए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) की जानकारी साझा करते हुए बताया कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एआई सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सक्षम शिक्षक अभियान के तहत राज्य में शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स और एआई



आधारित शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के प्रथम चरण की शुरुआत रायपुर से की जाएगी, जिसके बाद इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शिक्षकों को एआई प्रमाणन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गूगल फॉर एजुकेशन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा सके।

कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में 200 शिक्षकों की सहभागिता से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, कक्षा शिक्षण में एआई के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक-सक्षम और नवाचार आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शिक्षा से जोड़ना केवल एक पहल नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल शिक्षण पद्धतियों में गुणवत्ता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर नए युग के कौशल विकसित होंगे, जो उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एआई सक्षम शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को ढ्ढ आधारित प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों से सशक्त कर कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है - छत्तीसगढ़ को एक ऐसे ज्ञान-आधारित और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करना, जहाँ हर विद्यार्थी को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अवसरों से भरपूर शिक्षा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक सशक्त, आधुनिक और तकनीक-सक्षम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चार जिले के सहायक आयुक्त को शो-कॉज नोटिस

■ प्रमुख सचिव बोरा ने ली राज्य स्तरीय विभागीय बैठक

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक मंत्रालय में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, आय-व्यय तथा आगामी कार्ययोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने विभागीय योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सराहना की, वहीं विभिन्न मदों के बजट आबंटन को सदुपयोग न करने वाले चार जिले बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए आश्रम छात्रावासों की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। श्री बोरा ने निर्देशित किया कि अगले दो महीनों में छात्रावासों के मरम्मत, रंग-रोगन, शौचालय, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही छात्रावासों में अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी



निर्देश दिए गए। उन्होंने प्रोजेक्ट संकल्प के तहत विद्यार्थियों के सांस्कृतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को और मजबूत करने के लिए ध्यान और योग को भी शामिल करने की बात कही। इसके अलावा, सेप्टिक टैंकों की सफाई मैनुअल तरीके से न कराकर, नगरीय निकायों के माध्यम से सक्शन मशीनों से कराने के निर्देश दिए।

बैठक में छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष जताया गया। बताया गया कि नई व्यवस्था के तहत पिछले सत्र में 3.3 लाख विद्यार्थियों को माह दिसम्बर तक छात्रावृत्ति की 72 प्रतिशत राशि और 99 प्रतिशत राशि 31 मार्च तक, सुगमतापूर्वक समय पर सीधे विद्यार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर ग्राम सभाओं के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्वीकृत परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए आश्रम, छात्रावास भवन बनाने का प्रस्ताव भेजने से पहले स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र में पूर्व प्रस्तावित छात्रावासों का निर्माण अब प्राथमिकता से किया जाए। बैठक में एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालयों में एक भी सीट खाली न रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, पीएम जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष, देवगुड़ी एवं अखरा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता के साथ शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा त्वरित मुआवजा : केदार कश्यप



रायपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत अज्ञात वाहन से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और घायलों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। इस संबंध में परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नागरिकों से अपील की कि दुर्घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए योजना का लाभ उठाएं।

परिवहन विभाग ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। %सावधानी हटी, दुर्घटना घटी% के संदेश के साथ विभाग ने सुरक्षित यात्रा को जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय बताया है।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि कठिन समय में पीड़ित परिवारों को संबल भी देती है। योजना के अनुसार, हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 2 लाख रूपए तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

इस योजना के तहत मृतक के पति/पत्नी, माता- पिता, पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकते हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्वयं भी आवेदन करने के पात्र हैं।

पीड़ित या उनके परिजनों को सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में दुर्घटना की सूचना देनी होती है। इसके बाद निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एसडीएम कार्यालय में जमा करना होता है। सत्यापन के बाद मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

आवेदन के लिए एफआईआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चिकित्सकीय प्रमाणपत्र, पहचान एवं पता प्रमाण पत्र, संबंध प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक होती है।

फार्मेसी शिक्षा और शोध से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था : स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के अवसर पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित फार्मा अन्वेषण 2026 कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया।



कार्यक्रम की थीम "Future Pharma Ecosystem: Academia, Industry, Research, Regulatory and Practice के बीच समन्वय रही, जिसमें फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के बेहतर तालमेल पर विशेष चर्चा की गई।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि फार्मेसी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में इसकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ फार्मेसी शिक्षा और रिसर्च को भी प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने युवाओं और शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से ही हम बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अकादमिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे नए अवसरों का सृजन हो सके।

रायपुर-उरकुरा-मांढर रेलखंड हुआ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ रेल परिचालन की क्षमता बढ़ाने हेतु निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर-उरकुरा एवं उरकुरा-मांढर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत रायपुर-उरकुरा (लगभग 3 किलोमीटर, डबल लाइन) तथा उरकुरा-मांढर (लगभग 9 किलोमीटर, ट्रिपल लाइन) रेलखंड पर कुल 12 किलोमीटर लंबाई में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है, जो डबल लाइन समतुल्य लगभग 21 किलोमीटर के बराबर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के तहत अब तक कुल 21 किलोमीटर डबल लाइन समतुल्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत 14 नए



ऑटोमेटिक सिग्नल एवं 2 सेमी-ऑटोमेटिक सिग्नल स्थापित किए गए हैं। साथ ही कुल 80 डिजिटल एक्सल काउंटर लगाए गए हैं, जिनमें ड्यूल डिटेक्शन एवं मीडिया डाइवर्सिटी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ट्रेन की सटीक एवं रीयल-टाइम स्थिति का पता लगाया जा सकता है। रायपुर-उरकुरा खंड में अप एवं डाउन लाइनों पर 3-3 ऑटो सेक्शन तथा उरकुरा-मांढर खंड में अप, डाउन एवं मिड लाइन (द्विदिशीय) पर 4-4 ऑटो सेक्शन बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इंटर-स्टेशन ब्लॉक इंटरफेस ट्रांसमिशन के लिए यूनिवर्सल फेल-सेफ ब्लॉक इंटरफेस प्रणाली तथा उरकुरा-मांढर खंड में मिड लाइन के लिए डायरेक्शन सेटिंग पैनल की सुविधा भी प्रदान की गई है।

संरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समपार फाटक संख्या 417 पर एक नया ऑटो हाट भी स्थापित किया गया है, जिससे सिग्नलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और बेहतर हुई है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली लागू होने से अब एक ही ब्लॉक सेक्शन में एक ही दिशा में एक से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो गया है। इससे ट्रेनों की गति में वृद्धि, समय की बचत तथा लाइन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब ट्रेनों को आगे बढने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे परिचालन अधिक सुचारु एवं कुशल हो गया है रेलवे में सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा परिचालन की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिससे न केवल ट्रेनों की गति और संख्या में वृद्धि हो रही है, बल्कि यात्रियों को संरक्षित एवं विश्वसनीय यात्रा अनुभव भी सुनिश्चित हो रहा है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पीसीसी चीफ बैज का तीखा बयान

जंगलराज चल रहा है, असुरक्षित महसूस कर रही जनता

रायपुर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक दिन पहले सेजबहार में एक परिवार के साथ हुई लूट की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में जंगलराज चल रहा है। अपराध सरकार के नियंत्रण से बाहर है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में श्लोक से सरकारी स्कूलों की शुरुआत होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक बच्चों को पुस्तक उपलब्ध नहीं करवा पाए, ऋक्ष में एडमिशन नहीं हो रहा है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं, बच्चियों के लिए टायलेट नहीं है। क्या सरकार शिशु मंदिर बनाना चाहती है? स्कूल में श्लोक पढ़ाने की बजाए इस दिशा में सरकार होमवर्क करे, तो स्कूल बेहतर हो जाएगा।

वहीं आज असम, केरल और पुडुचेरी में हो रहे मतदान को लेकर



दीपक बैज ने कहा कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरी तरह से बदलाव का माहौल बना हुआ है। असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जवाब न देकर गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हिमंत विश्वा सरमा जेल जाएंगे।

महतारी वंदन के लिए केवायसी को अनिवार्य किए जाने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। केवायसी के नाम पर सरकार महिलाओं के नाम काटने की साजिश कर रही है।

नक्सलमुक्त पंचायतों को 1 करोड़ रुपए दिए जाने को लेकर बैज ने कहा कि सरकार ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों से वादा किया है। नक्सलमुक्त पंचायतों को 1 करोड़ रुपए देने हैं। सरकार कह रही है कि सभी जिले नक्सलमुक्त हो चुके हैं, तो 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। इसके लिए क्या पीएम मोदी से मुलाकात कर राशि मांगी गई है। कितने पंचायतों को देना है, या दे चुके सरकार स्पष्ट करे। इस सरकार का हर वादा जुमला है।

वहीं अंबिकापुर में मूर्ति अनावरण को लेकर उपजे विवाद पर दीपक बैज ने कहा कि सबका अपने-अपने स्थान पर सम्मान है। शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम पहले आना चाहिए। यदि कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया तो क्या गलत किया।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मोहला-मानपुर-अं. चौकी (छग.)

E-mail- eemohla-phe@cg.gov.in

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव गौरव उत्सव स्वर्णिम संकल्प

//ई-प्रोक्योरमेंट//

निविदा आंत्रण सूचना (रिस्क एंड कास्ट)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र "अ" में जल जीवन मिशन अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम/रेट्रोफिटिंग योजनांतर्गत जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी के विभिन्न विकासखंडों के विभिन्न ग्रामों में रिस्क एवं कास्ट में अधूरे छोड़े कार्य जिसमें UPVC/HDPE पाईप लाईन जोड़ने बिछाने, उच्चस्तरीय जलागार निर्माण, स्वीच रूम, उच्चस्तरीय जलागार के चारो ओर बाउंड्रीवॉल निर्माण, सबमर्सिबल पंप का प्रदाय एवं स्थापना कार्य, विद्युत विभाग (CSPDCL) से इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर स्थापना, क्लोरीनेटर रूम, घरों एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत नल कनेक्शन प्रदाय आदि एवं अन्य समस्त कार्य, टेस्टिंग, 03 माह का ट्रायल रन, 06 माह तक संचालन संधारण का कार्य (सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित, संलग्न शेड्युल अनुसार) की निविदाए दिनांक 06.04.2026 से ऑन लाईन पर आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्य के निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से दिनांक 13.04.2026 से डाउनलोड की जा सकती है तथा निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 27.04.2026 (शाम 5.30 बजे) तक है।

निविदा में जारी एस.ओ.आर. PHE दिनांक 01.06.2020 से लागू एवं संशोधन 05/2021.22 तक तथा PWD 2015 का दिनांक 07.04.2016 से लागू समस्त संशोधन सहित पर तैयार किया गया है।

क्रं.	निविदा कंमाक	सिस्टम कंमाक	विकासखण्ड	योजना/ग्राम का नाम	निविदा की लागत (रू.लाख में)	निविदा आंमत्रण का प्रकार
1	1	188528	चौकी	कातुलवाही	28.03	द्वितीय
2	2	188529	चौकी	पांगरी, खैरी, मांझीटोला	52.82	द्वितीय
3	3	188530	चौकी	मुंजाल, झिटिया, खड़खड़ी	61.38	द्वितीय
4	4	188531	मोहला	बोदाल, जोबटोला, दनगढ़, कुम्हली	111.39	द्वितीय
5	5	188532	मोहला	शेरपार, ककईपार, चांपाटोला	72.28	द्वितीय
6	6	188533	मानपुर	गोटुलमुंडा	21.51	प्रथम
7	7	188534	मानपुर	कनेली, कोरकट्टी, हनईकलकला	21.53	प्रथम
8	8	188535	मानपुर	घोटिया	75.57	प्रथम

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
मोहला-मानपुर-अं. चौकी (छ.ग.)

जी-262700086/10

युद्ध विराम से पश्चिम एशिया में बढ़ी शांति की उम्मीदें

शशांक

अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल रुक गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमति बन गयी है। हालांकि कुछ दिन पहले तक भी समझौता होना मुश्किल लग रहा था। ट्रंप ने तो यहां तक कहा दिया था कि एक सभ्यता समाप्त होने वाली है। ईरान भी युद्ध समाप्त न करने पर अड़ा हुआ था। उसका कहना था कि समझौते को लेकर बातचीत शुरू तो होती है, पर अमेरिका उसे बीच में समाप्त कर देता है और ईरान पर बमबारी शुरू हो जाती है। उस हिसाब से 15 दिनों का यह जो समय मिला है, वह शांति से सोच-विचार का समय है कि एक-दूसरे की कौन-सी बात माननी है और कौन सी नहीं। इस दौरान यदि स्थायी शांति के लिए रास्ता तैयार हो जाता है, तो यह राहत की बात होगी। हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि युद्ध विराम से स्थायी शांति हो जायेगी। यह समझौता संकेत देता है कि ईरान युद्ध समाप्ति की ओर है। यहां इस बात पर विचार करना भी जरूरी है कि जो ट्रंप एक दिन पहले ईरान को धमकी दे रहे थे, वह अचानक युद्ध विराम पर कैसे सहमत हो गये। दरअसल, ट्रंप की बातों से लोगों को यही लगा कि अमेरिका परमाणु हमले की दिशा में आगे बढ़ रहा है। या तो अमेरिका ईरान को नष्ट करने के लिए अपना खुद का परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, या ईरान ने जो अपने परमाणु एसेट, रिएक्टर छिपाकर रखे हुए हैं, उस पर गहराई तक मार करने वाले डीप पेनेट्रेशन बम से प्रहार करेगा। ट्रंप के इस बयान का आकलन शुरू हो गया था कि इसका दुनिया पर, खासकर ईरान के पड़ोसी देशों पर क्या असर होगा। भारत ने भी इस दिशा में सोचना शुरू किया कि अमेरिका के इस कदम से उसे क्या नुकसान होगा। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि पाकिस्तान, तुर्किये और मिस्र युद्ध रुकवाने के लिए बातचीत कर रहे थे। युद्ध विराम में इन तीनों की भूमिका है। चूंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छी दोस्ती है, सो मुनीर ने ट्रंप को समझाया होगा कि वह परमाणु हमले जैसा कदम न उठायें, क्योंकि ईरान का पड़ोसी होने के नाते उसे भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रेडिएशन के प्रभाव से समुद्र का पानी जहरीला हो जायेगा और लोगों की जान पर बन आयेगी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स की तरफ से भी ट्रंप पर दबाव पड़ना शुरू हो गया था और उन पर महाभियोग चलाने पर भी विचार किया जा रहा था। दरअसल, अमेरिकी नहीं चाहते कि ट्रंप के गलत कदमों से विश्वयुद्ध जैसे हालात बनें। तो अपने लोगों के दबाव के कारण भी 15 दिन का युद्ध विराम घोषित हुआ। इस बात पर भी दुनिया की नजर होगी कि युद्ध विराम के बाद आगे क्या होता है, क्योंकि ईरान बार-बार कह रहा है कि उसका काफी नुकसान हुआ है और उसका भुगतान यदि अमेरिका नहीं करता है, तो वह होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कर लगाकर इस नुकसान की भरपाई करेगा। इस युद्ध विराम को ईरान की जीत और अमेरिका-इस्राइल की नैतिक हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐसी सोच सही नहीं है, बल्कि अमेरिका, इस्राइल और ईरान, तीनों को यह सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से क्षेत्र में शांति आये। इस समय यदि दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी जीत के दावे किये जायेंगे, नफा-नुकसान की बातें की जायेंगी, तो हो सकता है कि फिर से कोई पेच फंस जाये और युद्ध विराम विफल हो जाये। इसलिए, अभी इस तरह की बातों से बचने की जरूरत है। अब चूंकि युद्ध विराम हो चुका है, और सारा झगड़ा ही यूरेनियम संवर्धन को लेकर शुरू हुआ था, तो स्वाभाविक है कि शांति वार्ता में इस बारे में भी चर्चा होगी। हां, यह देखना होगा कि इस चर्चा में कौन-कौन से देश शामिल होते हैं।

आइए, मिलकर नारी शक्ति को सशक्त करें?

नरेंद्र मोदी



21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जनभागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। यह ऐसा समय है, जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है, जो हमारे लोकतंत्र को अधिक व्यापक एवं और अधिक प्रतिनिधिक बनाए।

संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा व विधानसभाओं, संस्थाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग-अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे।

असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं, और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विशु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है।

हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ-साथ दुनियाभर में इन त्यौहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ। बाबासाहब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे।

ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की है। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है।

इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारीशक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारीशक्ति मिसाल बन रही है।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है, जब माताओं-बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलते हैं।

इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोत्तरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है।

लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है। इस कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है।

इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में सुधार भी होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है।

अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए।

विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार-बार दोहराया गया है। अगर अब भी हम इसे आगे टालते हैं, तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं,

जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा, बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी।

यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और मिलकर ही इसे साकार करना है।

यही हमारी नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं।

ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता में होती है। संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारीशक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

पुराण दिग्दर्शन ....



सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(ख) स (इन्द्र) यत्र त्रिशीषर्षाणं त्वाष्ट्रं विश्वरूपं जघान

(शतपथ 1।2।3।2)

(ग) इन्द्रो वै त्रिशिरसं त्वाष्ट्रमहन् ।

(ताण्ड्य 17।5।1)

अर्थात् (क) त्वष्टा का पुत्र तीन सिर और छः आँखों वाला था, उसके मुख भी तीन थे। क्योंकि वह इस प्रकार अद्भुत रूप वाला था इसी लिए उसका (अन्वर्थ) विश्वरूप ऐसा नाम पड़ गया था। दूसरा सुरा काभ आता उसका एक मुख सोम (याज्ञिक रस) पीने के लिये, (= शराब) पीने के लिये और तीसरा अन्न खाने के लिये था। उस विश्वरूप से इन्द्र द्वेष रखता था, अतः इन्द्र ने उसके वह तीनों शिर काट डाले। जो लोम पीने वाला मुख था, वह कपिञ्जल नामक पक्षी हुवा । जो सुरा पीने का वाला था वह कलविङ्क नामक पक्षी हुवा और जो अन्न खाने वाला था वह तित्तिर हो गया। (ख) उस इन्द्र ने त्वष्टा के बेटे, तीन सिर वाले विश्वरूप को मार डाला। (ग) इन्द्र ने तीन सिर वाले त्वष्टापुत्र को मार डाला।

पौराणिक-स्वरूप

(क) त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका ।
सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्य्यवान् ।।44।
तं वव्रिरे सुरगणा दौहित्रं द्विषतामपि ।।45।।

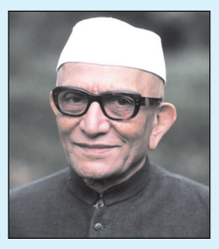
(श्रीमद्भागवत 6 ।6)

(ख) तस्यासन्त्रिश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत!
सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम: ॥1॥
स वै बहिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकै: ।
ग्रददद्यस्य पितरो देवा: सप्रश्रयं नृप! ॥2॥
स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान्प्रति।
यजमानोऽवहद् भागं मातृस्नेहवशानुग: ॥3॥
तदेवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वर:।
आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्रुषा ॥4।।

क्रमशः ...

मोरारजी देसाई

अनुराग गुप्ता



भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात के भदेली गांव में 29 फरवरी, 1896 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जबकि 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। कांग्रेस के बेहद करीबी लोगों में से एक मोरारजी देसाई को पार्टी छोड़ने के बाद 81 वर्ष की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था और 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

गैर-कांग्रेसी के तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने वाले मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। आपको बता दें कि देश में एकलौते मोरारजी देसाई ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। देश ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा।

गांधीवादी विचारधारा के पक्के समर्थक रहे मोरारजी देसाई खादी को देश का वस्त्र मानते थे और उन्होंने हमेशा ही स्वदेशी चीजों का समर्थन किया। उनका हमेशा से मानना था कि एक दिन देश को खादी पर आना ही पड़ेगा।

इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी खूब सुनाई देता है कि जब मोरारजी देसाई का एक पत्रकार साक्षात्कार कर रही थी तो उस वक्त मोरारजी देसाई ने उस पत्रकार से पूछ लिया कि तुम गांधीजी को कितना याद करती हो गांधी तक तो पहनती नहीं हो। मुझे देखो, मैं हमेशा खादी पहनता हूं। इस पर पत्रकार ने जवाब दिया कि यह तो मंहगा है तो मोरारजी देसाई ने मजे में पत्रकार को जवाब दिया कि जो तुम पहनी हो वो कौन सा सस्ता है ? कुछ भी कहिए, एक दिन देश को तो खादी पर आना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के थे भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई।

कांग्रेस में रहते हुए अक्सर उनका नाम सुनाई देता था प्रधानमंत्री पद के लिए मगर जब वक्त आता था तो वह इस दौड़ में पिछड़ जाते थे। हालांकि, कांग्रेस से अलग होने के बाद साल 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई तो उन्हें ये मौका मिला और यह पहला मौका था जब देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने।

1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई कार्यकाल रहा। हालांकि चौधरी चरण सिंह के साथ मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ने के बाद से और प्रधानमंत्री बनने से पहले तक मोरारजी देसाई कांग्रेस में बने रहे थे।

25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल के बाद, जनता पार्टी ने जून 1977 में शानदार जीत के साथ एक अप्रत्याशित चुनाव जीता। जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए मोरारजी देसाई को चुना। दो साल की राजनीतिक अशांति और जनता पार्टी के भीतर कई विभाजनों के बाद, देसाई ने अविश्वास मत को टालने के लिए 15 जुलाई, 1979 को अपने इस्तीफे की घोषणा की।

राष्ट्रप्रमुख पद की मर्यादा भूल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प

मनोज कुमार अग्रवाल

अमेरिकी नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को धमकाते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया. ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर हमले की चेतावनी दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट और ब्रिज डे होगाज होर्मुज स्ट्रेट खोलो, नहीं तो नर्क में जीओगे.यह जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस सप्लाई रूट्स में से एक है, जो फरवरी के अंत में अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से लगभग बंद है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. ट्रंप ने होर्मुज को लेकर ईरान को कई बार धमकी दी है और इस समुद्री मार्ग को खोलने का अल्टीमेटम दे चुके हैं. उन्होंने होर्मुज को खोलने में अमेरिका की मदद नहीं करने के लिए यूरोपीय व नाटो सहयोगियों पर भी नाराजगी जताई है. ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दी कि अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है. अपने इस पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से उम्मीद नहीं की जाती.

हालांकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर कभी कोई मुकदमा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दर्ज होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय उनकी भाषा में जो गिरावट स्पष्ट स्पष्ट परिलक्षित है, कम से कम उसका विश्व समुदाय को विरोध करना चाहिए।

दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजरायल को जंग छेड़े छह सप्ताह हो चुके हैं, जिसमें कई बार जीत का दावा करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जीत के लक्षण नहीं दिखा पाए। बल्कि बार-बार युद्धविराम की अवधि को बदलते हैं और साथ ही उनकी धमकियां भी बदल रही हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन के ऐलान से शुरु हुआ यह युद्ध अब नागरिकों को निशाने पर लेने की धमकियों पर उतर आया है। रविवार को ईस्टर के मौके पर अपने सोशल मीडिया



प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि 48 घंटों में होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग खोलो वर्ना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने लिखा कि मंगलवार को ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर व्यापक हमले हो सकते हैं, और इसे संघर्ष का निर्णायक क्षण बताया। लेकिन यह सब इसी तरह की शालीन भाषा में नहीं लिखा गया, बल्कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। और यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने इस तरह सार्वजनिक तौर पर अपशब्द कहे हों। इससे पहले उन्हें पत्रकारों से चर्चा के दौरान या भाषण देते हुए भी अपशब्द बोलते देखा गया है। यह किसी लिहाज से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और वैश्विक नेताओं को खुलकर इसकी भर्त्सना करना चाहिए। नरेन्द्र मोदी से इसकी शुरुआत हो तो कितना अच्छा रहेगा।

अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया. उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह रवैया अमेरिका के सहयोगियों को उससे दूर कर रहा है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान को युद्ध अपराध की धमकी देने जैसा बताया. ट्रंप की पूर्व सहयोगी मार्जरी टेलर ग्रीन ने भी उनके बयान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं. उन्होंने अमेरिकी प्रशासन के लोगों से दखल देने की अपील की. टेलर ग्रीन ने कहा कि यह युद्ध बिना उकसावे के शुरू किया गया और इससे निर्दोष लोगों की जान जा रही है.

वैसे संयुक्त राष्ट्र में ईरानी ई मिशन ने ट्रंप की की नवीनतम टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में नागरिकों के जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यदि संयुक्त राष्ट्र की अंतरात्मा जीवित होती, तो वह युद्ध भड़काने तो वह युद्ध भड़काने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खुली और बेशर्म धमकी पर चुप नहीं रहती। ट्रंप इस क्षेत्र को एक अंतहीन युद्ध में घसीटना चाहते हैं। इसमें कहा गया, यह नागरिकों को आतंकित करने के लिए प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावा है और युद्ध अपराध करने के इरादे का स्पष्ट प्रमाण है। इसमें आगे कहा गया- अंतरराष्ट्रीय समुदाय और सभी राज्यों का यह कानूनी दायित्व है कि वे युद्ध अपराधों के ऐसे जघन्य कृत्यों को रोकें। उन्हें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। कल बहुत देर हो जाएगी। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष गलिबाफ ने कहा कि ट्रंप के लापरवाह कदमों से अमेरिका के हर परिवार को एक जीती-जागती नरक में धकेला जा रहा है, हमारा पूरा क्षेत्र जल उठेगा क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हैं। गुलिबाफ के इस बयान से असहमत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह अपने बयान बदल रहे हैं, उसमें यही लगता है कि पटकथा कोई और लिख रहा है, केवल संवाद अदायगी ट्रंप की है। क्योंकि अपशब्द वाले बयान के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार से कहा, मुझे लगता है कि सोमवार को समझौता होने की अच्छी संभावना है, वे (ईरान) अभी बातचीत कर रहे हैं। तो ट्रंप को लगता है कि ईरान अब भी उनसे बात कर समझौता करेगा, जबकि ईरान की सबसे बड़ी सैन्य कमांड यूनिट खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा, अगर आम लोगों पर हमले दोहराए गए, तो हमारे अगले हमले और जवाबी कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़े पैमाने पर होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान केवल धमका नहीं रहा है, अपनी बात पर अमल भी कर रहा है। अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों समेत इजरायल पर ईरान के हमलों को कोई रोक नहीं पा रहा है, वहीं अमेरिका के लड़ाकू विमानों पर हुए हमले और एक अमेरिकी पायलट के लापता होने की घटना ने भी जाहिर कर दिया है कि अमेरिका उतना भी ताकतवर देश नहीं है, जितना बड़ा उसका हौव्वा खड़ा किया गया है। ईरान की पहाड़ियों में लापता पायलट को बचाने का दावा ट्रंप ने किया है, हालांकि ईरान ने कहा है कि उसने बचाव के लिए आए सैन्य दस्ते पर भी हमला किया है। अब किसका दावा सही है और किसका गलत, यह तय नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना तो नजर आ ही रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका को वैसी ही चोट पड़ रही है, जो पहले इराक, अफगानिस्तान, क्यूबा और वियतनाम में पड़ चुकी है।

आपको पता है कि 2019 में ट्रंप ने खुद एक पोस्ट में प. एशिया में अमेरिका की सैन्य दखलंदाजी और युद्ध को गलत ठहराया था, क्योंकि उसमें अरबों डॉलर खर्च हुए और सैनिकों का नुकसान हुआ। लेकिन अब संभवतः एपस्टीन फाइल्स के खुलासे के दबाव में ट्रंप ने पूरी दुनिया को युद्ध की बर्बादी में झोंक दिया है। अपनी गलती मानने की जगह रोजाना बेतुके, निर्लज्ज बयानों से उसे सही भी ठहरा रहे हैं। ईरान में परमाणु हथियार और सत्ता बदलने के नाम पर शुरु किया गया युद्ध मीनाब की मासूम बच्चियों का कातिल बना और उसके बाद ईरान की अधोसंरचना पर हमले ही किए जा रहे हैं, कम से कम 30 विश्वविद्यालयों और कई अस्पतालों, दवा कारखानों को बारुद से ढेर कर दिया गया है। यह सीधे-सीधे मानवता के खिलाफ अपराध है, जिसे रोकने के लिए वैश्विक समुदाय को मिलकर आवाज उठानी चाहिए।

आज का इतिहास

1869 कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 से 9 की।
1874 14 वें ब्रिटिश गोल्फ ओपन: मुंगे पार्क ने मुससेलबर्ग लिंक पर 159 को गोली मारी।
1875 आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी।
1919 मैक्सिकन क्रांति के नेता एमिलियानो जैपटा को सियुदाद अयला, मोरेलोस को गोली मार दी गई थी।
1925 फ्रेंच प्रधानमंत्री एडॉर्ड हेरिएट ने इस्तीफा दिया।
1925 एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा उपन्यास द ग्रेट गैट्सबी को पहली बार प्रकाशित किया गया था।
1926 मिस्र के राजा फुआद ने मिस्र के संसद का उद्घाटन किया
1939 इटालियन सेना ने अल्बानिया पर कब्ज़ा किया।
1941 द्वितीय विश्व युद्ध-क्रोएशिया स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी, जिसमें उस्ताई नेता एंटे पावेलिक के रूप में एक्सिस शक्तियों की कठपुतली सरकार के प्रमुख थे।
1953 मेलबॉर्न नाइट्स को मेलबोर्न में क्रोएशिया एससी के रूप में स्थापित किया गया।
1960 24 वीं गोल्फ मास्टर्स चैंपियनशिप: अर्नोल्ड पामर जीतता है, 282 की शूटिंग करता है।
1963 पनडुब्बी यूएसएस थ्रेशर के समुद्र में डूबने से 119 अमेरिकी नाविकों की मौत।
1964 पोलो ग्राउंड्स के खेल स्टेडियम का विघटन न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ।
1970 अपने बैंडमेट्स के साथ व्यावसायिक असहमति के बीच, पॉलमेकार्टनी ने बीटल्स से अपने प्रस्थान की घोषणा की।
1971 फिलाडेल्फिया में दिग्गज स्टेडियम खोला गया।
1972 44 वा वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजिल्स के डोरोथी चांडलर मंडप में आयोजित किया गया।
1973 पाकिस्तान ने पुराने संविधान को निरस्त किया।
1985 मैडोना ने न्यूयॉर्क सिटी से अपना पहला वर्जिन टूर कॉन्सर्ट दौरा शुरू किया।
1988 महान सेटो ब्रिज जापान में यातायात के लिए खोला गया।
1992 नागोर्नो-करबाख युद्ध-कम से कम 40 अर्मेनियाई नागरिकों का मारागा, अजरबैजान में हमला हुआ।
1993 दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता क्रिस हानी की हत्या कर दी गई।
1995 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और देश के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन।

विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा और सत्ता के नए समीकरण

योगेश कुमार गोयल

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों ने देश की राजनीति को उबाल पर ला दिया है। केरल से लेकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी तक सियासी हलचल अपने चरम पर है। रैलियों की गूंज, वादों की बरसात और आरोप-प्रत्यारोप के तीखे तीरों के बीच लोकतंत्र का यह उत्सव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने-अपने एजेंडे, घोषणापत्र और रणनीति के साथ मैदान में है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस बार का चुनाव केवल सरकार बनाने का साधन नहीं बल्कि बीते पांच वर्षों के कामकाज का जनमत संग्रह और आने वाले राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण है।

इन पांच राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर लगभग 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि 116 लोकसभा सीटों के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह राजनीतिक रणक्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी को प्रभावित कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम भी बेहद दिलचस्प है, असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में वोट डाले जाएंगे। नतीजे 4 मई को घोषित होंगे और उसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। इस बार का चुनावी परिदृश्य कई स्तरों पर जटिल और बहुआयामी है। सत्ताधारी दल जहां अपने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और 'डबल इंजन' जैसे नारों के सहारे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक खामियों को मुद्दा बनाकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। यह संघर्ष अब केवल सत्ता का नहीं रहा बल्कि विचारधारा, नीतियों और विकास के मॉडलों की प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है।

सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल, जहां राजनीतिक तापमान सबसे ज्यादा है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 6.44 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा बनाए रखा था जबकि भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार मुकाबला और अधिक तीखा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 'बंगाल मॉडल', महिला सशक्तिकरण योजनाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा 'डबल इंजन' सरकार के वादे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रही है। रोजगार, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यहां मुकाबला बेहद कांटे का होगा, एक



तरफ ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत दांव पर है तो दूसरी ओर भाजपा के लिए यह पूर्वी भारत में विस्तार का सुनहरा अवसर है।

असम का चुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। 126 सीटों वाली विधानसभा में 2.25 करोड़ मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यहां मुख्य सवाल यही है कि क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वापसी का रास्ता तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। वहीं विपक्ष सीएए-एनआरसी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सक्रियता ने इस चुनाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। असम में परिणाम न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूर्वोत्तर भारत में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेंगे।

दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की राजनीति अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का प्रभाव इतना गहरा है कि राष्ट्रीय दलों की भूमिका सीमित हो जाती है। 234 सीटों वाली विधानसभा में 5.67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में डीएमके गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपने 'द्रविड़ मॉडल', सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन महंगाई, बिजली संकट और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। इसके अलावा अभिनेता विजय की पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना एक नया समीकरण बना सकता है, खासकर युवा मतदाताओं के बीच।

केरल में 140 सीटों के लिए 2.7 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। यहां का चुनाव पारंपरिक रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाता रहा है लेकिन पिछले चुनाव में वाम मोर्चे ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। इस बार यदि वह तीसरी बार सत्ता में आता है तो यह एक नया राजनीतिक अध्याय होगा। वाम मोर्चा अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के मॉडल को प्रमुखता दे रहा है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर हमलावर है। भाजपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है।

पुदुचेरी भले ही छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो, लेकिन यहां की राजनीति बेहद संवेदनशील और निर्णायक है। 30 सीटों वाली विधानसभा में 9.44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहां गठबंधन राजनीति का महत्व सबसे अधिक है, जहां छोटे-छोटे वोट अंतर भी सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सत्ता हासिल की थी और इस बार भी वह अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत हैं। इन सभी राज्यों में एक समान बात यह है कि वोट प्रतिशत और सीटों का समीकरण हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार मामूली वोट अंतर भी भारी सीट अंतर में बदल जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने चुनावी अभियान को एक नई दिशा दी है, जहां नैरेटिव की लड़ाई केवल मैदान में नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जा रही है।

चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार कोई एक मुद्दा हावी नहीं है। रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप में सामने आ रहे हैं। यही विविधता इन चुनावों को और अधिक जटिल और रोचक बनाती है। राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इन राज्यों से आने वाली 116 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यदि भाजपा असम में अपनी पकड़ बनाए रखती है, पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है और दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करती है, तो उसकी राष्ट्रीय स्थिति और सुदृढ़ हो सकती है। वहीं, यदि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अपनी सत्ता बरकरार रखती है तो ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की प्रमुख धुरी बनी रह सकती हैं। केरल में वाम मोर्चे की जीत वामपंथी राजनीति के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगी जबकि तमिलनाडु में डीएमके की निरंतरता द्रविड़ राजनीति की दिशा तय करेगी।

कुल मिलाकर, यह चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। मतदाता इस बार खामोश जरूर हैं लेकिन उनकी चुप्पी के भीतर गहराई से सोच-विचार और निर्णय की प्रक्रिया चल रही है। 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा कि किसने जनता की अपेक्षाओं को समझा और किसे आत्ममंथन की आवश्यकता है। लोकतंत्र का यह महापर्व एक बार फिर यह सिद्ध करने जा रहा है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और वही निर्णय देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है।

पंजाब में अमित शाह का प्रतिभा खोज अभियान?

हरीश गुप्ता

पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार अब धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेज और आक्रामक तरीके से हो रहा है। अमित शाह की 'ओपन डोर' नीति कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक तरह का वैचारिक खालीपन बनती जा रही है। असम और पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर लड़ाई लड़ने के बाद अब पार्टी का इरादा साफ है, अगर सिस्टम को हरा नहीं सकते, तो उसे चलाने वालों को ही अपने साथ मिला लो। लेकिन पंजाब भाजपा के पुराने और लंबे समय से जुड़े नेता असहज और चिंतित हैं। उन्होंने दशकों तक 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा लगाया और अब अपने को 'कांग्रेस युक्त भाजपा' के बीच पा रहे हैं।

प्रमुख नेताओं पर नजर डालिए। सुनील जाखड़, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में पीढ़ियों से कांग्रेस की छाप रही है, अब भाजपा की कमान संभाले हुए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने सिर्फ पार्टी नहीं बदली, बल्कि सीधे केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। और फिर 'महाराजा' कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर अपने पूरे राजनीतिक खेमे के साथ भाजपा में शामिल हो गए।

दिल्ली से जो संदेश आ रहा है, वह बिल्कुल साफ और व्यावहारिक है, 'जीत ही सबसे बड़ी वफादारी है।' यहां प्रतिभाओं की तलाश ऐसे हो रही है जैसे किसी कॉरपोरेट कंपनी में बड़े पदों के लिए लोगों को ढूंढ़ा जाता है। चाहे आम आदमी पार्टी के नाराज सांसद हों जो अपने लिए सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हों, या अकाली दल के पुराने नेता जो बदलती हवा को भांप रहे हों, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।

यह असम वाला मॉडल ही है, बस अधिक



आक्रामक है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उन नेताओं से भरा है जो कभी कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। अब पंजाब भी उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने मुश्किल दौर में भी पार्टी का साथ निभाया, यह स्थिति विडंबनापूर्ण है।

उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वही लोग भाजपा में आकर अहम फैसले लेते दिख रहे हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं पार्टी अपने मूल विचारों से दूर होकर सिर्फ वोट जुटाने की राजनीति तक सीमित न हो जाए। अमित शाह का यह दांव बड़ा और जोखिम भरा है। उनका भरोसा है कि बाहर से आए प्रभावशाली नेता मिलकर उन स्थानों पर सफलता दिला सकते हैं,

जहां पुराने कार्यकर्ता अब तक कुछ नहीं कर पाए, खासकर किसान आंदोलन प्रभावित इलाकों में। अभी हालात ऐसे हैं कि पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, माहौल में आगे बढ़ने की होड़ है और धीरे-धीरे पार्टी की पुरानी पहचान कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है।

हिमंत के लिए अग्निपरीक्षा है असम चुनाव, क्या मिलेगी सफलता?

प्रभाकर मणि तिवारी

असम में इस बार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के लिए अग्निपरीक्षा साबित होंगे। यह कहना ज्यादा सही होगा कि यह मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सरकार के पांच साल के कार्यकाल पर जनमत संग्रह होगा। राज्य की 126 सीटों के लिए नौ अप्रैल को मतदान होगा।

वैसे, तो उनको पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन उनके नेतृत्व में पिछले दो चुनाव से बेहतर प्रदर्शन से ही यह उपाधि सार्थक साबित होगी। विकास के तमाम दावों के बावजूद हिमंत की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा को अपने बूते बहुमत दिलाना है।

राज्य में बहुमत का आंकड़ा 64 है, लेकिन वर्ष 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 60 सीटों तक ही पहुंच सकी थी। लेकिन उस समय हिमंत न तो मुख्यमंत्री का चेहरा थे और न ही मुख्यमंत्री। वर्ष 2016 में अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने वाली भाजपा ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 2021 के बाद हिमंत इस कुर्सी पर बैठे थे। इसलिए इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पांच साल इस कुर्सी पर रहने के बाद वो अपने बूते भाजपा को बहुमत दिलाने में कामयाब रहेंगे?

वर्ष 2016 में 89 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने 29.5 फीसदी वोटों के साथ 60 सीटें जीतकर अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। वर्ष 2021 में उसको मिले वोट तो बढ़ कर 33.21 फीसदी तक पहुंच गए। लेकिन तब 93 सीटों पर लड़ने के बावजूद वह 60 सीटें ही जीत सकी थी। इसी तरह वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों की तादाद सात थी। लेकिन उसके बाद क्रमशः 2019 और 2024 में यह नौ तक ही पहुंच सकी। अब इस बार परिसीमन की वजह से मुस्लिम-बहुल सीटों की तादाद में कमी और सरकार की कल्याणमूलक योजनाओं के भरोसे पार्टी अपने बूते बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने की उम्मीद कर रही है। परिसीमन के कारण राज्य में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 29 से घट कर 22 रह गई है। यानी वैसी सात सीटें घट गई हैं जहां



तत्कालीन पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से आने वाले मुसलमान निर्णायक स्थिति में हो सकते थे।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पार्टी अपने बूते बहुमत हासिल करने में कामयाब रहती है तो उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर नहीं रहना होगा। पहले ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। अपने बूते बहुमत हासिल करने के बाद नई सरकार अपने एजेंडे को मजबूती से लागू कर सकती है। इसके साथ ही वह अपने सहयोगी दलों से सौदेबाजी भी कर सकती है।

चुनावी नतीजों से यह भी साबित होगा कि सरमा की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए गए कथित अल्पसंख्यक विरोधी अभियानों और स्वदेशी बनाम बंगाली मिया मुसलमान का नैरेटिव सियासी तौर पर कितना कामयाब रहा है। अकेले अपने बूते पार्टी को बहुमत दिलाने से वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, यह भी साबित कर सकेंगे कि असम की सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा को किसी गठजोड़ की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री हिमंता लंबे समय से मियां मुसलमानों के खिलाफ मुखर रहे हैं। इसकी वजह से राज्य में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण तेज हुआ है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी के आक्रामक बयानों के अलावा मुख्यमंत्री के कथित भ्रष्टाचार को ही अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाया है।

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति रखने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा रिनिकी पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने से चुनाव से ठीक पहले राजनीति गरमा गई है।

शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि इस चुनाव में भाजपा को विपक्ष की ओर से किसी कड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन के बाद अब उसकी राह आसान नहीं लग रही है।

लंबे समय तक जारी कयासों के बाद कांग्रेस ने अखिल गोगोई की राइजोर दल के साथ हाथ मिलाया है। विपक्षी गठबंधन में अब इन दोनों पार्टियों के अलावा लिरिनज्योति गोगोई की असम जातीय परिषद और आल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं। अहोम समुदाय के इन तीनो नेताओं के एक गठजोड़ में शामिल होने से खासकर ऊपरी असम में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ गई है। इलाके में 50 सीटें हैं। यहां जीत ही सत्ता का रास्ता खोलती है। उस इलाके में अहोम समुदाय के वोटर कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं।

राज्य के जेन जी यानी युवा वोटर इस बार राजनीतिक दलों की बजाय उम्मीदवारों को उनकी छवि और कामकाज के आधार पर वोट देने का मन बना रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के लगभग ढाई करोड़ वोटरों में से 29 फीसदी यानी 73 लाख से ज्यादा वोटर 19 से 29 साल के आयु वर्ग में हैं। इसके अलावा करीब 62 लाख वोटरों की उम्र 30 से 39 साल के बीच है।

जहां तक चुनाव अभियान का सवाल है भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। दूसरी ओर, कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी ही स्टार प्रचारक रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार मतदान से पहले तेजी से बदले समीकरणों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इससे हिमंत सरमा की चुनौती भी बढ़ी है। अब देखना होगा कि वो इस अग्निपरीक्षा में कितने कामयाब रहते हैं।

केरल चुनाव 2026 का बदलता परिदृश्य

कांतिलाल मांडोत

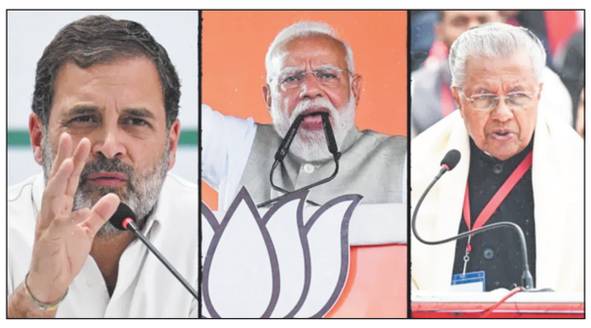
दक्षिण भारत का राज्य केरल हमेशा से अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान के लिए जाना जाता रहा है। यहां की राजनीति विचारधाराओं के टकराव से अधिक सामाजिक संतुलन और विकास के मुद्दों पर केंद्रित रही है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे उभरकर सामने आए हैं जिन्होंने राज्य की चुनावी दिशा को नई बहसों की ओर मोड़ दिया है। इनमें धर्मांतरण का प्रश्न प्रेम विवाह को लेकर विवाद और राजनीतिक दलों की रणनीतियां प्रमुख हैं।

राज्य में इस समय पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा भी मुकाबले में है। इस त्रिकोणीय संघर्ष ने चुनाव को और रोचक बना दिया है।

धर्मांतरण और प्रेम विवाह का मुद्दा इस बार सबसे अधिक चर्चा में है। कुछ संगठनों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पिछले एक दशक में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब कुछ अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई।

ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी महत्वपूर्ण हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म चुनने और विवाह करने का पूरा अधिकार है। इस कानूनी स्थिति के बावजूद राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस तरह की फिल्मों और कथाओं को राज्य की छवि खराब करने वाला बताया है।

केरल की सामाजिक संरचना भी इस चुनाव को खास बनाती है। यहां लगभग तीस प्रतिशत मुस्लिम आबादी है जबकि बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ एक मजबूत ईसाई समुदाय भी मौजूद है। खासतौर पर उत्तरी और मध्य जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रभाव अधिक है और इन्हीं क्षेत्रों में



कई सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मांतरण का मुद्दा भले ही चर्चा में हो लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सीधे मतदान के निर्णय को प्रभावित करे। केरल के मतदाता परंपरागत रूप से शिक्षा स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि कई बार बड़े विवाद भी चुनावी परिणामों में अपेक्षित असर नहीं डाल पाते।

भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी का मानना है कि धार्मिक पहचान और सुरक्षा के मुद्दे पर वह मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। लेकिन चुनौती यह है कि केरल में अब तक भाजपा को व्यापक जनसमर्थन नहीं मिल पाया है। यहां की राजनीति लंबे समय से वाम और कांग्रेस के बीच ही घूमती रही है।

दूसरी ओर वाम मोर्चा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चुनाव मैदान में है। खासकर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने उसे मजबूत आधार दिया है। राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और यह वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2021 के चुनाव में भी महिलाओं का झुकाव वाम मोर्चे की ओर देखा गया था।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी इस बार वापसी की कोशिश में हैं। वे सरकार की कथित विफलताओं और प्रशासनिक मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि उन्हें भी यह समझना होगा कि केवल विरोध के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं है।

कानून व्यवस्था का मुद्दा भी चुनावी बहस का हिस्सा है। विपक्ष समय समय पर राज्य में बढ़ते अपराधों और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाता रहा है। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी उपलब्धियों को सामने रखती है। आम जनता के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है लेकिन यह कितना असर डालेगा यह कहना कठिन है।

दलित और पिछड़े वर्गों की भूमिका भी इस चुनाव में अहम है। केरल में इन वर्गों की संख्या भले ही बहुत अधिक न हो लेकिन उनका वोट कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। सभी दल इन वर्गों को साधने के लिए अलग अलग योजनाएं और वादे कर रहे हैं।

जहां तक भाजपा के सत्ता में आने की संभावना का सवाल है तो यह अभी भी चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी उपस्थिति जरूर बढ़ाई है लेकिन उसे व्यापक जनाधार बनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल की राजनीतिक संस्कृति और मतदाताओं की सोच अन्य राज्यों से अलग है जहां केवल एक मुद्दे के आधार पर बड़ा बदलाव आना मुश्किल होता है। इस चुनाव में असली मुकाबला एक बार फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच ही नजर आता है। हालांकि भाजपा कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है और चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करना उसके लिए कठिन चुनौती बना हुआ है। अंततः कहा जा सकता है कि केरल का चुनाव केवल धर्म या किसी एक विवाद का चुनाव नहीं है। यह राज्य की सामाजिक संरचना विकास मॉडल और राजनीतिक परंपराओं का सम्मिलित प्रतिबिंब है। मतदाता यहां भावनाओं से अधिक विवेक से निर्णय लेते हैं और यही इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। 2026 का चुनाव भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और परिणाम यह तय करेंगे कि केरल किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति

नीरज कुमार दुबे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे के दौरान जो कुछ हुआ, उस पर उनकी तीखी नाराजगी, मालदा की शर्मनाक घटना पर उच्चतम न्यायालय की कड़ी और असहज कर देने वाली टिप्पणियां और कूच बिहार की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचंड प्रहार यह साबित करने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। देखा जाये तो हालात इतने बदतर हैं कि देश की संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और न्याय के सर्वोच्च मंदिर उच्चतम न्यायालय की चिंता एक ही दिशा में इशारा कर रही है कि पश्चिम बंगाल आज अराजकता और भय के माहौल में जी रहा है।

हम आपको याद दिला दें कि पिछले माह बंगाल में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नाराजगी केवल एक प्रोटोकॉल का मुद्दा नहीं थी, बल्कि यह उस प्रशासनिक अव्यवस्था का प्रतीक थी जो राज्य में गहराई तक पैठ बना चुकी है। उस घटना ने दर्शाया था कि शासन तंत्र किस हद तक असंवेदनशील और मनमानी का शिकार हो चुका है। जब देश की प्रथम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम नागरिक की सुरक्षा और सम्मान की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। वहीं मालदा की घटना ने तो इस अराजकता को और भी भयावह रूप में उजागर कर दिया। सात न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक घेर कर रखना, उन्हें भोजन और पानी तक नहीं मिलने देना और प्रशासन का पूरी तरह निष्क्रिय बने रहना, यह पूरे सिस्टम के पतन की कहानी है। उच्चतम न्यायालय ने इसे राज्य प्रशासन की पूर्ण विफलता बताया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह न्यायिक व्यवस्था को डराने का सुनियोजित प्रयास है। न्यायालय ने सीबीआई या एनआईए से जांच कराने का निर्देश देकर यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार पर भरोसा करने की स्थिति नहीं बची है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार की रैली में इस घटना को तृणमूल कांग्रेस का महा जंगलराज करार देते हुए बिल्कुल सही तस्वीर सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि यह चुनाव भय और भरोसे के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वह सरकार है जिसने बंगाल को हिंसा, भ्रष्टाचार और असुरक्षा में धकेल दिया है, और दूसरी तरफ वह संकल्प है जो कानून का राज स्थापित करने की बात करता है। प्रधानमंत्री का यह आश्वासन कि इस बार भय भागेगा और हर अपराध का हिसाब होगा, बंगाल की जनता के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने भी इस बिगड़ती स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यहां तक कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों को तैनात रखने का निर्णय यह दर्शाता है कि आयोग किसी भी कीमत पर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग दो हजार से ढाई हजार कंपनियों की तैनाती, ईवीएम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल और आपराधिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई, यह सब इस बात का प्रमाण है कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र की असली परीक्षा है। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों को दी जा रही पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सत्ता का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा। अपराधियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई, यहां तक कि थाना प्रभारी का निलंबन, यह दिखाता है कि अब जवाबदेही तय होगी और हर गलती का हिसाब लिया जाएगा। देखा जाये तो आज बंगाल की जनता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे तय करना है कि वह भय और हिंसा के इस चक्र को जारी रखेगी या बदलाव का रास्ता चुनेगी। यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं बल्कि व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अवसर है। हर मतदाता का वोट इस अराजकता के खिलाफ एक मजबूत हथियार बन सकता है।

जब गंगा-सरस्वती में विवाद हुआ



भारत में बहने वाली गंगा और सरस्वती नदियां वास्तव में स्वर्ग की देवीयां हैं। जो परसपर एक-दूसरी के शाप के कारण वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुईं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की तीन पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती थीं। एक बार लीला स्वरूप विष्णु जी ने गंगा जी के प्रति विशेष अनुराग प्रदर्शित किया। फलस्वरूप सरस्वती के मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो गया। इस पर उन्होंने भगवान विष्णु जी को खरी-खोटी सुनाईं, जिस पर विष्णु भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब सरस्वती ने गंगा जी को भी दुर्वचन कहने शुरू किए, तो भगवान उठकर प्रासन्द से बाहर चले गए। इस पर सरस्वती का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने गंगा के केश पकड़ लिए। लक्ष्मी जी पास में बैठीं अब तक शांत थीं। जब उन्होंने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया, तो सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानकर उनका अपमान कर दिया तथा वृक्ष रूप हो जाने का शाप दे दिया। इधर, गंगा जी ने निरापराध लक्ष्मी को दंडित होते देख सरस्वती को भूतल पर जाकर नदी हो जाने का शाप दे दिया। सरस्वती भी कहां पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने क्रोध से गंगा जी को शाप दिया कि वह भी भूतल पर मृतक प्राणियों की अस्थियां ढोने वाली नदी के रूप में प्रवाहित हों। गंगा तथा सरस्वती का विवाद काफी समय तक चलता रहा। कुछ समय पाकर भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लौटे, तो पत्नियों की कलह और शाप का विवरण हुआ। विष्णु जी ने लक्ष्मी को शांत वृति, सहनशीलता और उदारता की प्रशंसा की तथा उन्हें सब में श्रेष्ठ बताया। भगवान विष्णु ने केवल लक्ष्मी को ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा। गंगा तथा सरस्वती के मर्यादा उल्लंघन करने के कारण विष्णु जी ने उनका त्याग करने का निर्णय लिया। वियोग की आवश्य मानी स्थिति से व्यथित होकर दोनों ही कातर स्वरों में शापों को शीघ्र निपटाने का उपाय पूछने लगीं।

सपने बताएँ आपकी जिंदगी



आधुनिक विज्ञान का यह मानना है कि मनुष्य अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने सपनों में पूरा करता है जबकि ज्योतिष-शास्त्र का यह कहना है कि सपने मनुष्य को भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। जिस प्रकार पशु-पक्षी बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को पहले से ही भाँप जाते हैं ठीक वैसे ही मनुष्य द्वारा रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। बस जरूरत है उन सपनों को ठीक ढंग से समझने की।

- स्वप्न में किसी स्त्री को बाल धोते हुए अथवा संवारते हुए देखना शीघ्र ही किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का सूचक होता है। लेकिन स्वयं कंघी करना शरीर में किसी चोट की सूचना देता है।
- स्वप्न में किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखना ठीक नहीं माना गया है जबकि बदसूरत या किसी अपंग व्यक्ति को देखना, रुके हुए कार्य में सफलता का सूचक होता है।
- किसी की शवयात्रा अथवा श्मशान में अंत्येष्टि क्रिया को देखना, परिवार में जल्दी ही मांगलिक कार्यों तथा आर्थिक लाभ का परिचायक है।
- मनुष्य अगर स्वप्न में वर्जिश करता हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही किसी रोग का शिकार हो जाता है।
- सपने में अगर आप खुद को आकाश में विचरण करते हुए दिखाई दें तो परिवार में किसी सदस्य की मानहानि की सूचना देता है। लेकिन खुद का धरती पर घूमना शीघ्र ही रोजगार प्राप्ति में सहायक होता है।
- स्वप्न में ज्योतिषी के पास जाना अथवा ज्योतिष से संबंधित कोई भी कार्य करना संतान को किसी-न-किसी रूप में कष्ट में डालता है।
- नींद में स्वयं को झाड़ू लगाते हुए देखना धन हानि या चोरी की सूचना देता है।
- स्वप्न में स्वयं को बारिश में भीगते हुए देखना हर तरह की व्याधि और संकट से मुक्ति का संकेत देता है।
- स्वप्न में बैंड या शहनाई का बजते हुए देखना दु:खद स्थितियों के आगमन का संकेत देता है।
- नींद में रोटी का खाना स्वयं के बीमार पड़ने का संकेत देता है, वहीं गरीब लोगों को रोटी का बाँटना आर्थिक स्थिति में वृद्धि करता है।
- सोते हुए विवाह का सेहरा पहनते हुए देखना पारिवारिक और विवाहित जीवन में अलगाव तथा झगड़े का संकेत देता है।
- आईने में अपना अक्स देखना अचल धन-संपत्ति प्राप्ति का संकेत देता है।
- स्वयं को स्वप्न में जूते-चप्पलों से पिटते हुए देखना शीघ्र ही व्यक्ति के मान-सम्मान में वृद्धि करता है। लेकिन किसी दूसरे को जूते से पीटना धन हानि और मान हानि की ओर संकेत करते हैं।

जब भगवान सूर्य का जन्म हुआ

सत्ताधिकार के लिए देवताओं और असुरों में शत्रुता थी। इसी बात को लेकर एक बार दैत्यों और देवताओं में भयानक युद्ध हुआ। यह संघर्ष अनेक वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। वे पराजित हो गए। वन-वन भटकने लगे। देवताओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। उनकी ऐसी दुदर्शा देख कर उनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति दुखी रहने लगे।

एक बार देवर्षि नारद घूमते-घूमते कश्यप जी के आश्रम की ओर आ निकले। वहां अदिति और महर्षि कश्यप को व्याकुल देख कर उन्होंने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। अदिति बोली-देवर्षि! दैत्यों ने युद्ध में देवताओं को पराजित कर दिया है। इन्द्रादि देवगण भटक रहे हैं। हमें उनकी रक्षा करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। नारद जी बोले- माते। इस संकट से बचने का केवल एक उपाय है। आप उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करें। उनसे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान प्राप्त करें। केवल भगवान सूर्य नारायण के तेज के समक्ष ही दैत्य पराजित हो सकते हैं और देवताओं की रक्षा हो सकती है। अदिति सूर्य नारायण की तपस्या करने लगी। अदिति को तप करते अनेक वर्ष बीत गए। भगवान सूर्य नारायण ने अदिति की तपस्या भंग करने के लिए प्रयास किए पर वह तपस्या में लीन रही। अंत प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए व बोले- हे देवि। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मनवांछित वरदान मांगों। अदिति बोली- सूर्यदेव। मेरी केवल यह विनती है कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं की रक्षा करें। अदिति की बात कर सूर्यदेव बोले- तथास्तु देवि ऐसा ही होगा। अदिति का वरदान देकर सूर्यदेव अंतरध्यान हो गए।

एक बार महर्षि कश्यप और अदिति कुटिया में बैठे थे। तभी किसी बात पर क्रोधित होकर कश्यप ने अदिति के गर्भस्थ शिशु के लिए मृत शब्द का प्रयोग कर दिया। कश्यप ने जैसे ही मृत शब्द का उच्चारण किया। तभी अदिति के शरीर से दिव्य प्रकाश पुंज निकला। उस प्रकाश पुंज को देखकर कश्यप मुनि भयभीत हो गए और सूर्य देव से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। तभी एक दिव्य आकाश्वाणी हुई। 'मुनिवर! मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूं। मेरी आशा से एक दिव्य बालक जन्म लेगा। जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के पश्चात ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित हो जाएगा।'

महर्षि कश्यप और अदिति ने वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश पुंज की स्तुति आरंभ की। उचित समय आने पर उसमें से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। यही बालक 'आदित्य' और



'मार्तण्ड' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। आदित्य वन-वन जाकर देवताओं को एकत्रित करने लगे। आदित्य के तेजस्वी और बलशाली स्वरूप को देख कर इन्द्रादि देवता उत्साहित हो गए तथा उन्होंने संगठित होकर, दैत्यों पर आक्रमण कर दिया।

आदित्य को देव सेना का सेनापति बनाया गया। आदित्य को देव सेना का सेनापति बनाया गया। आदित्य के तेज और बल के आगे दैत्य अधिक समय तक टिक नहीं सके। शीघ्र ही उनके पांव उखड़ गए। वे अपने प्राण बचा कर पाताल भाग गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से देवताओं का स्वर्ग पर पुन: अधिकार हो गया। सभी देवताओं ने आदित्य को जगत पालक के रूप में स्वीकार कर लिया तथा आदित्य ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित होकर ब्रह्माण्ड का कार्य संचालन करने लगे।

मानसिक शांति पाने के लिए....

मनुष्य को धन-धान्य, यश, सम्पत्ति आदि प्राप्त हो जाएं पर मानसिक शांति प्राप्त न हो तो वह सब वैभव उसके लिए कष्टप्रद हो जाते हैं। अत: चित्त शांति के लिए निम्नलिखित प्रयोग करें।

प्रतिदिन प्रात:काल स्नान करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर उत्तर की तरफ मुख करके बैठें। सामने एक पट्टे पर श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर ऊंकार का एक चित्र विराजमान करें। यह परमात्मा का एक परम शान्तिदायक प्रतीक है, ऐसी भावना करें।

प्रतीक के सामने गाय के घी का दीपक और धूपबत्ती जलाकर दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर तथा धूपबत्ती को अपने दाहिने हाथ की ओर रखें।

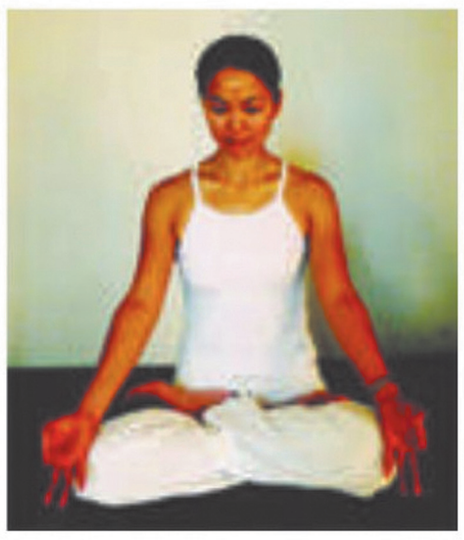
इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर मस्तक को झुकाकर 'ऊँ नम: सिद्धेभ्य:,ऊँ नम: सिद्धेभ्य:,ऊँ नम: सिद्धेभ्य:' बोलते हुए प्रणाम करें।

इसके पश्चात आगे लिखाहुआ श्लोक बोलकर मंगल भावना करें।

सर्वे वै सुखिनःसंतु, सर्वेसंतु निरामयाः।

सर्वे भद्राणिपश्यंतु मा कश्चिद धुःखभाग् भवेत।।

सभी सुखी हों, सभी रोगरहित बनें, सभी कल्याणमय वस्तुओं को देखें तथा कोई भी दुखी न हों। इसके बाद 'ऊँ शांति ऊँ' इस मंत्र की दस माला का जप करें. यह माला सूत की अथवा स्फटिक की होनी चाहिए तथा



उसका संस्कार भी कर लेना चाहिए। रात को सोने से पहले 'ऊँ नम: सिद्धेभ्य:,ऊँ नम: सिद्धेभ्य:, ऊँ नम: सिद्धेभ्य:' मंत्र बोलकर तीन बार भगवान को नमस्कार करें। इस प्रकार प्रयोग करने से मानव को मानसिक शांति प्राप्त होती है एवं कई प्रकार की परेशानियां भी कम होती हैं। इस उपाय से आप मानसिक शांति का अनुभव करने लगेंगे.यह क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होगी.

पौधे, जो लाते हैं घर में सुख-समृद्धि

हरियाली फेंगशुई के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। फेंगशुई के अनुसार स्वस्थ और सुंदर पौधे आपके घर में खुशियां लाते हैं और घर के हर कोने को उत्साह और उमंग से सरोबार कर देते हैं।

फेंगशुई में पौधों को नौ आधारभूत सुरक्षा सावधानियों में से एक माना गया है। इसलिए घर के खाली हिस्सों में पौधे लगा देना चाहिए।



कैसे पौधे लगाएं?

- चढने वाली बेलें जिन्हें क्लाइमबर्स कहा जाता है जैसे- मनी प्लांट को कोने में लगाकर उस जगह की उदासीनता को कम किया जा सकता है।
- घर के दक्षिण-पूर्व कोने को धन और समृद्धि का कोना माना जाता है, इसलिए यहां चौड़े पत्तियों वाले पौधे लगाना चाहिए।
- मुरझाए हुए या सूख गए पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है।
- घर के सामने वाले हिस्से में कांटेदार या नुकीले पत्तों वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। वे नकारात्मक ऊर्जा को सहयोग करते हैं।

इन छोटी-छोटी बातों पर अमल करके आप प्राकृतिक हरियाली और सुख का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ पेड़-पौधों हमारे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक हैं।

बारिश कराने में भी सिर्फ पेड़-पौधों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अत: हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधों को लगाकर हरियाली बढ़ानी चाहिए।

घर में बांसुरी रखने के 8 फायदे



* आप नहीं जानते होंगे, बांसुरी को घर में रखने के ये 8 फायदे...

बांसुरी भगवान श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय है। बांसुरी कृष्णजी को प्रिय होने के कारण उसको पकृति का अनुपम वरदान है। वास्तु और फेंगशुई के अनुसार बांसुरी को अगर घर, दुकान में रखा जाए है तो इसके कई लाभ मिलते हैं। आइए जानें...

* ज्योतिष के अनुसार बांसुरी का इस्तेमाल अगर सोच समझकर किया जाए तो यह हमें कई प्रकार के दोषों से बचाती है।
* बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं।
* और जब बांसुरी को बजाया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि घरों में शुभ चुम्बकीय प्रवाह का प्रवेश होता है।
* फेंगशुई विद्या के अनुसार बांसुरी घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। यह उन्नति और प्रगति दोनों देने में बहुत सहायक है। इस प्रकार बांसुरी प्रकृति का एक अनुपम वरदान है।
* यदि सोच-समझकर इसका उपयोग किया जाए तो दोषों का बिना किसी तोड़-फोड़ के निवारण कर अशुभ फलों से बचा जा सकता है।
* बांसुरी बांस से बनी होती है तथा इसके पौधे को दिव्य माना जाता है। अत: घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है।
* ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी से परेशान रहता हैं, बांसुरी उसकी सारी मुश्किलें आसान कर सकता है।
* ज्यो व्यक्ति काफी मेहनत के बाद भी अपने बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर पाते उनके लिए बांस से बनी यह बांसुरी उन्नति और समृद्धि दोनों देने में सक्षम है। अत: उन्हें भगवान श्रीकृष्ण का पूजन करते हुए अपने दुकान की छत पर दो बांसुरी चिपकानी चाहिए या टांग देनी चाहिए।

जाने क्या है शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप का सत्य

सृष्टि में नर और नारी की समानता का प्रतीक है भगवान शिव का अर्द्धनारीश्वर स्वरूप। जानें उसके पीछे की कहानी।

ब्रह्मा की समस्या

कहते हैं जब सृष्टि की संरचना के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य का निर्माण किया तो उन्हें समझ आया कि ये तो एक शीघ्र अंत होने वाली रचना है क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुरुष बनाये। सृष्टि को चलाने के लिए संतति की आवश्यकता है और उसके लिए स्त्री की, पर वो है ही नहीं। तब अपनी समस्या के समाधान के लिए वो शिव की शरण में पहुंचे और कठोर तप किया। ब्रह्मा की कठोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उनकी समस्या के हल के फल में उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रगट किया। इस रूप में वे आधे शिव थे और आधे शिवा। इस तरह उन्होंने मानव को प्रजनन शील बनने क प्रेणना देकर सृजन का संदेश दिया।

स्त्री पुरुष समानता

इसके साथ ही उन्होंने अपने इस रूप से पुरूष और स्त्री की समानता के महत्व का भी उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों पकृति का अभिन्न अंग हैं और एक के बिना भी इसका विकास संभव नहीं है। अर्धनरनारीश्वर की आराधना का अर्थ है शिव अर्थात पुरुष और स्त्री यानि शक्ति का एका होना।

क्या है शिव और शक्ति का संबंध

शक्ति शिव की अभिभाज्य अंग हैं, यदि शिव नर के प्रतीक हैं तो शक्ति नारी की। वे एक दुसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अकर्ता हैं, यानि वे संकल्प मात्र करते हैं, संकल्प सिद्धी शक्ति ही करती हैं। अगर शिव कारण हैं तो शक्ति कारक हैं, शक्ति जागृत अवस्था हैं जबकि शिव सुशुप्तावस्था। शक्ति मस्तिष्क हैं और शिव हृदय हैं।

रत्न पहनने पर भी लाभ क्यों नहीं?

अपनी ग्रह बाधाओं को दूर करने एवं ऐच्छिक कार्यों की सफलता के लिए मनुष्य रत्नों को धारण प्राचीन काल से ही करता आया है। आज जो मनुष्य एक या दो रत्नों को धारण किए हुए रहते हैं, फिर भी उन्हें दुखी देखा गया है, वे अनेक कठिनाइयों से संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों?

शायद आप सोचेगें कि रत्न प्रभावशाली नहीं है या ज्योतिषी पंडित आदि ने गलत बताया है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो इसलिए होता है कि या तो वे नकली रत्न धारण किए होते हैं या रत्न दोष पूर्ण होते हैं अथवा विधिवत धारण किए हुए नहीं होते हैं। यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने ग्रह से संबंधित सही रत्न को धारण न किया हो।

यह ठीक है कि आप ज्योतिषियों के बताए अनुसार विधिपूर्वक शुभ दिन या मुहूर्त में रत्न धारण करते हैं, परन्तु किसी-किसी की आदत होती है कि अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर दूसरी उंगली में डाल लेना या मेज पर निकाल कर नचाना। इससे उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि उंगली से निकालकर पुन: पहनने के कारण ज्योतिषी के द्वारा बताया गया मुहूर्त और दिन बदल जाता है। इसी प्रकार किसी को दिखाने के लिए अपनी उंगली से बार-बार अंगूठी निकालना भी अनुचित है।

रत्न धारण करते समय कुछ सावधानियां रखी जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा:

धारण किए जाने वाले रत्न के स्वामी ग्रह और लग्नेश में मित्रता हो, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी अपनी महादशा या अंतर्दशा में मारकेश के रूप में कार्य करते हैं। ये भारी देह कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो इनके रत्न न धारण करें बल्कि इन ग्रहों को पूजा और दान आदि से शांति करें। शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ धारण न करें जैसे माणिक्य के साथ हीरा, नीलम व गोमेद निषिद्ध हैं क्योंकि सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं।

मोती के साथ गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। मूंगा के साथ हीरा, नीलम, व गोमेद न पहनें, पन्ना को मोती के साथ में न पहनें। बृहस्पति और राहु आपस में शत्रु हैं, अत: पुखराज के साथ गोमेद और हीरा धारण नहीं करना चाहिए। हीरा के साथ माणिक्य, मूंगा, व पुखराज नहीं पहनें। नीलम के साथ माणिक्य, मूंगा और पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। गोमेद और माणिक्य, मोती व मूंगा साथ न पहनें। लहसुनिया के साथ ऐसा कोई निषेध नहीं है।

रत्न धारण करते समय संबंधित ग्रह के मंत्र का जप 108 बार करना चाहिए एवं शुभ दिन को धारण करना चाहिए जैसे- माणिक्य रविवार को धारण करना चाहिए। साथ में ऊं घृणि सूर्याय नाम: मंत्र का जाप करना चाहिए। माणिक्य स्वर्ण में जड़वाना चाहिए। मोती चांदी में पहनें। मूंगा ताम्बे में ऊं अं अंगारकाय नम: मंत्र के साथ मंगलवार को धारण करना चाहिए। पन्ना स्वर्ण व चांदी में ऊं बुं बुधाय नम: मंत्र के साथ बुधवार को पहनना चाहिए। पुखराज स्वर्ण में बृहस्पतिवार को ऊं बृं बृहस्पतये नम: मंत्र के साथ पहनें। हीरा स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम में ऊं शुं शुक्राय नम: मंत्र जाप कर शुक्रवार को धारण करना चाहिए।

नीलम लोहा या पंच धातु में शनिवार को ऊं शुं शनैश्चराय नम: के साथ पहनें। गोमेद अष्टधातु या चांदी में जुड़वाकर शुक्रवार या शनिवार को ऊं रां राहुवे नम: मंत्र जप कर धारण करें। लहसुनिया चांदी में ऊं कें केतवे नम: मंत्र के साथ बुधवार या शनिवार को धारण करना चाहिए।

रत्न जड़ी अंगूठी को धारण करने से पूर्व उसे शुद्ध करने के लिए कम से कम 24 घंटे तक कच्चे दूध या गंगा जल में डुबो कर रखें। अंगूठी धारण करने का शुभ समय सूर्योदय से एक घंटे तक होता है परन्तु बुधवार के अतिरिक्त शेष दिनों में एक घंटे तक होता है परन्तु बुधवार के अतिरिक्त शेष दिनों में दोपहर में अभिजित मुहूर्त भी शुभ माना गया है।

धूप, दीप, अगरबत्ती जला कर उस ग्रह की उपासना करके पूर्व की ओर मुंह करके अंगूठी पहननी चाहिए। स्नानादि द्वारा स्वच्छ एवं पवित्र होकर रत्न धारण करना चाहिए। बीमारी की स्थिति में रत्न नहीं धारण करें। इस प्रकार उक्त सावधानियों को ध्यान में रख कर रत्न धारण किया गया हो तो इच्छित लाभ प्राप्ति में संशय नहीं रहता।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भाजपा ने हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया: नितिन नबीन



नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को कहा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में कोई मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। मीडिया से बातचीत में नितिन नबीन ने कहा कि प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, कहीं कोई मतभेद नहीं है। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा में पद की शपथ लेंगे। उन्होंने आगे कहा, भाजपा ने हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया है, और यही कारण है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं। सभी निर्णय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने पिछले महीने बिहार विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। जो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था। जेडीयू प्रमुख राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।

पुडुचेरी सीएम एन. रंगास्वामी ने डाला अपना वोट



पुडुचेरी। गुरुवार सुबह से पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के मतदान हुए। अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक, एन. रंगास्वामी गुरुवार को वोट देने मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने मतदान केंद्र तक अपनी मोटरसाइकिल से जाने की अपनी पुरानी परंपरा को इस बार भी कायम रखा। मुख्यमंत्री थट्टनचावडी और मंगलम विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं दोनों ही सीटों से जीतूंगा। मेरे लिए सीटों की संख्या से ज्यादा सरकार बनाना जरूरी है। वोट डालने जाने से पहले रंगास्वामी ने थट्टनचावडी में स्थित श्री सदुरु अप्पा पैथियम स्वामीगल तिरुकोविल मंदिर में पूजा-अर्चना की। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का मोटरसाइकिल से जुड़ाव 1991 से है।

आज जारी हो सकता है बंगाल में भाजपा का घोषणापत्र



कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र 10 अप्रैल को जारी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में इसे जारी करेंगे। इस घोषणापत्र में समाज के सभी वर्गों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाजपा के इस संकल्प पत्र में कई बड़े वादे शामिल किए जा सकते हैं। पार्टी महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक मदद देने की योजना बना रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज का इंतजाम होगा। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। महिलाओं की शिक्षा के लिए नए कॉलेज और बेहतर इलाज के लिए ज्यादा अस्पताल खोलने का वादा भी इसमें शामिल है।

सुनेत्रा की निर्विरोध जीत के लिए उम्मीदवार वापस लें कांग्रेस



मुंबई। महाराष्ट्र के बरामती विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात की और आग्रह किया कि उनकी चाची, एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, की निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार को वापस ले। सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बातचीत कर कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने का अनुरोध किया था। कांग्रेस ने पहले कहा था कि वह केवल तब चुनाव से पीछे हटेगी जब जनवरी में विमान हादसे में मृत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के मामले में एफआईआर दर्ज होगी, जिससे बरामती में उपचुनाव आवश्यक हुआ। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह अपने उम्मीदवार को वापस लेकर चुनाव निर्विरोध कर दें। सुप्रिया सुले ने ट्वीट में कहा कि अजीत पवार हमेशा कांग्रेस के साथ घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते थे।

अब्दुल्ला ने भारत की इजराइल से दोस्ती पर उठाये सवाल



श्रीनगर। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच भले संघर्षविराम हो गया हो लेकिन इस मुद्दे पर कश्मीर में जमकर राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भारत की इजराइल से दोस्ती पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थक रही हैं। वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए कह रही हैं कि पाकिस्तान ने एक विश्व युद्ध होने से बचा लिया। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस संघर्ष की असली चाबी अब भी अमेरिका के हाथ में है। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उमर ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इजरायल को काबू में नहीं रखा, तो यह सीजफायर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि मौजूदा टकराव ईरान पर थोपा गया है।

ममता बनर्जी की बंगाल की सत्ता से विदाई तय है : प्रधानमंत्री

■ **बंगाल में पीएम ने दी छह गारंटी; सबका साथ, सबका विकास और लुटेरों का हिसाब होगा भाजपा का नया नारा**



कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में तीन बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सामान्य नहीं, बल्कि बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता इस बार के चुनाव में ममता सरकार को हटाने वाली है। पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास नारे को दोहराते हुए कहा कि सबका हिसाब लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह चुनाव विकसित बंगाल की मजबूत नींव रखने का चुनाव है और इसका पहला तथा सबसे अहम कदम इस निर्दयी सरकार को सत्ता से बाहर करना होगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया।

पीएम मोदी ने देश की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जहां देश के कई राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं टीएमसी की सरकार बंगाल को पीछे धकेल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मतदाताओं से बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य को विकास के रास्ते पर लाने के लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार की छह गारंटियों को बताया।

पहली गारंटी- भय की जगह भरोसा कायम करेंगे।

दूसरी गारंटी- भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजेंगे।

तीसरी गारंटी- भ्रष्टाचार और अपराध की फाइलें खुलेंगी।

चौथी गारंटी- कानून सबका हिसाब करेगा।

पांचवीं गारंटी- घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे।

छठी गारंटी- सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ।

पीएम मोदी ने कई मुद्दों को लेकर ममता सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में मत्स्य पालन और सी-फूड के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य आज भी मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारी मांग के बावजूद बंगाल को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों से मछली आयात करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी टीएमसी सरकार आपको मछली जैसी बुनियादी चीज भी उपलब्ध नहीं करा पाई। यह उनकी गलत नीतियों का स्पष्ट उदाहरण है।

पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का कुल मछली उत्पादन और समुद्री निर्यात दोगुना हुआ है, लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार के कारण यह प्रगति नहीं हो पाई।

युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ दोहरा विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और जहां नौकरियां हैं, वहां भी बाहरी घुसपैठियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार है और उन्हें टीएमसी के मंत्रियों द्वारा लूटा जा रहा है।

औद्योगिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक समय हल्दिया जैसे इलाकों में देशभर से लोग काम करने आते थे, लेकिन अब यहां के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में घुसपैठियों की फैक्ट्री चल रही है, फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और पशु तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की राजनीति डर और भय पर आधारित है।

यह चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद पीएम मोदी का राज्य का दूसरा दौरा है। इससे पहले 5 अप्रैल को उन्होंने कूचबिहार से अपने अभियान की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार को घेरा था और 'भय बनाम भरोसा' का नारा दिया था।

पीएम ने टीएमसी सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लेकर तीखा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी को पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि वह प्रधानमंत्री से जुड़ी योजनाओं का नाम बदल देती है या उन्हें लागू ही नहीं करती।

पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का नाम बदल दिया गया, जिससे कई वास्तविक लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे राज्य के गरीबों को नुकसान हुआ है। उन्होंने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ पीएम शब्द होने के कारण इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया गया, जिससे गरीब और बुजुर्ग इलाज की सुविधा से वंचित रह गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी नेताओं की राजनीतिक नाराजगी उनसे हो सकती है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि संविधान और जनता द्वारा दिया गया पद है।

राजनीतिक दृष्टि से इन रैलियों को बेहद अहम माना जा रहा है। हल्दिया को नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, जहां भाजपा अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहती है। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल में पार्टी दोबारा अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है।

बीरभूम जिले के सूरी में आयोजित रैली भी खास महत्व रखती है, क्योंकि यह इलाका टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां भाजपा संगठनात्मक नेटवर्क और सत्ता विरोधी माहौल के सहारे अपनी पकड़ बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

भाजपा हल्दिया की सभी 16 विधानसभा सीटें जीतेगी : शुभेंदु



कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में जोश और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। हल्दिया में आयोजित जनसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त करते हुए दावा किया कि इस साल भाजपा हल्दिया के सभी 16 विधानसभा सीटें जीतकर जीत का परचम लहराएगी। जनसभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा मैं पीएम मोदी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस जिले में भाजपा पहले से ही 16 में 15 सीटों पर जीत रही थी। इस साल कमल का फूल सभी 16 सीटों पर खिलेगा। इस दावे के साथ भाजपा ने हल्दिया जिले में अपनी ताकत और लोकप्रियता को लेकर स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह तैयार है। शुभेंदु अधिकारी की रैली में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी भीड़ ने उत्साह और जोश के साथ उनके समर्थन में नारे लगाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने युवाओं के सपनों को कुचला है और प्राइवेट सेक्टर का नामोनिशान मिटा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने और तुष्टिकरण की नीति में लगी हुई है। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार में भर्ती ट्रांसपेरेंट, समयबद्ध और पूरी तरह निष्पक्ष होगी। कोई कमीशन, रिश्वत या भेदभाव नहीं होगा।

केरल में वेणुगोपाल का बड़ा दावा

यूडीएफ 100 पार करेगा पिनारयी से तंग है जनता



तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को दावा किया कि केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) 100 का आंकड़ा पार कर लेगा। गुरुवार को मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि लोग पिनारयी विजयन के मुख्यमंत्री रहते हुए तंग आ चुके हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने विजयन को जनविरोधी और अहंकारी बताया। उन्होंने एलडीएफ सरकार पर सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले के दोषियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया।

वेणुगोपाल ने कहा कि हम चुनाव में भारी जीत हासिल करेंगे। हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे। राज्य में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। वे बदलाव के पक्षधर हैं। वे पिछले दस वर्षों से पिनारयी विजयन के मुख्यमंत्री रहते हुए तंग आ चुके हैं। इस चुनाव में जनता के सामने सवाल यह है कि क्या इस जनविरोधी, अहंकारी मुख्यमंत्री को पांच और साल तक सत्ता में रहना चाहिए? लोग कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यही प्रतिक्रिया हमें हर तरफ से मिल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आप देख सकते हैं कि भगवान अय्यप्पा का सोना चोरी हो गया है। यह सरकार सोने की चोरी के मामले में अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है। वे खुद इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने अंबलपुझा के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद ये टिप्पणियां कीं। असम और केरल राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गुरुवार सुबह 7 बजे से महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले के लिए मतदान शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। एक चरण में हो रहे विधानसभा चुनावों में अपना वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े हैं। केरल में 140 निर्वाचन क्षेत्रों में 883 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 26 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। राज्य भर में पंजीकृत 2,69,53,644 मतदाताओं में से 1,38,27,319 महिला मतदाता हैं और पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,31,26,048 है।

खेल
प्रमुख समाचार

एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप आयुष शेट्टी का शानदार प्रदर्शन

नईदिल्ली। बैडमिंटनएशिया चैंपियनशिप में



भारत के लिए गुरुवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहा। जहां युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, वहीं दिग्गज खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी।

विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर काबिज आयुष शेट्टी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए चीनी ताइपे के चि यू जेन को सीधे गेम में 21-16, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली और भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा।

अब आयुष का अगला मुकाबला इंडोनेशिया के तीसरी वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी से होगा। यह मुकाबला उनके लिए बड़ी परीक्षा साबित होगा, जहां उन्हें अपनी फॉर्म बरकरार रखनी होगी।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू को महिला एकल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वांग झियि ने 21-18, 21-8 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।

चोट से वापसी कर रहे एच एस प्रणय को भी निराशा हाथ लगी। उन्हें चीन के वेंग होंग यांग ने 21-12, 21-19 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया।

मिश्रित युगल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो को मलेशिया की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेन तांग जी और तो ई वेई के खिलाफ 21-13, 21-14 से हार का सामना करना पड़ा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 931 अंक लुढ़का निफ्टी 23775 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार (9 अप्रैल) को गिरावट में बंद हुए। एक दिन पहले सीजफायर की घोषणा के बाद ईरान और अमेरिका में तनाव फिर बढ़ने की खबरों से बाजार में बिकवाली देखी गई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स गिरावट के साथ 77,319.33 अंक पर खुला। खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी देखी गई लेकिन बाद में बिकवाली बढ़ गई। कारोबार के दौरान यह 76,347 अंक तक गिर गया था। अंत में यह 931.25 अंक या 1.20 फीसदी की गिरावट लेकर 76,631.65 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी कमजोर शुरुआत के साथ 23,909 अंक पर खुला। बुधवार को यह 23,997 पर बंद हुआ था। वहीं, कारोबार के दौरान यह 23,682 अंक तक गिर गया और अंत में 222.25 अंक या 0.93 फीसदी गिरकर 23,775 पर बंद हुआ।

एक दिन की गिरावट के बाद कच्चे तेल में जोरदार उछाल

नईदिल्ली। सीजफायर के बाद राहत की उम्मीद कर रहे तेल बाजार को फिर झटका लगा है। एक दिन की गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया है, जिससे वैश्विक सप्लाई पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि पश्चिम एशिया से तेल की सप्लाई को लेकर अब भी चिंताएं बनी हुई हैं। ईरान का कहना है कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रोजाना केवल 12 जहाजों को गुजरने देगा और उनसे टोल वसूलेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस अहम समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोला जाएगा और टोल फ्री बनाया जाएगा। दोनों पक्षों के अलग-अलग रुख से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड करीब 2.86% बढ़कर 97.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया डब्ल्यूटीआई क्रूड 3.56% चढ़कर 97.77 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।

सब्सिडी बढ़ी, फिर भी खाद कंपनियों पर संकट

नईदिल्ली। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी है, लेकिन इससे कंपनियों को पूरी राहत नहीं मिली है। एंटीक स्टॉक ब्रोकरेज की रिपोर्ट कहती है कि हालात अभी भी चुनौती भरे हैं। कच्चे माल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि कंपनियों का खर्च कम नहीं हो पा रहा। यानी सरकार ने मदद तो की है, लेकिन दबाव अभी भी बना हुआ है। सरकार ने नाइट्रोजन, फॉस्फेट और सल्फर पर सब्सिडी करीब 10 प्रतिशत बढ़ाई है, जबकि पोटाश की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस फैसले से सरकार का खर्च भी बढ़ गया है। पहली छमाही में करीब 415 अरब रुपये खर्च होंगे, जो पिछले साल से ज्यादा है। पूरे साल के लिए गैर-यूरिया खाद पर 540 अरब रुपये का बजट रखा गया है। डीएपी पर सब्सिडी भी बढ़ाई गई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह बढ़ोतरी अभी भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है।

15,400 टन रसोई गैस लेकर भारत पहुंचा जहाज

नईदिल्ली। नवी मुंबई के समुद्री तट से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच रसोई गैस (एलपीजी) लेकर एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत पहुंच गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 को जानकारी दी कि 15,400 टन एलपीजी लेकर आ रहा एक बड़ा जहाज सफलतापूर्वक नवी मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। यह उपलब्धि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इस जहाज ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया, जहां फिलहाल ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। ग्रीन आशा नाम का यह भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच गया है।

बैंकों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते गोल्ड लोन

सतीश सिंह

पिछले दो वर्षों में सोने की कीमत में हुई बढ़ोतरी और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों में बदलाव के कारण गोल्ड लोन में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गयी है। अब ये नियम अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गये हैं। स्वर्ण ऋण मूल्य (एलटीवी) की संरचना को स्तरीकृत किया गया है, सोने की मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और कड़ी कर दी गयी है। गोल्ड मेटल लोन की अवधि 180 दिनों से बढ़ाकर 270 दिनों की कर दी गयी है। ये बदलाव गोल्ड लोन को अधिक आसान और सुरक्षित बनाते हैं, जिससे गोल्ड लोन वितरण में तेज वृद्धि दर्ज हो रही है। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का विस्तार इतना बढ़ गया है कि यदि इसे अन्य ऋण पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाये, तो कई बैंकों की वास्तविक ऋण वृद्धि 100 से 400 आधार अंकों तक कम हो सकती है।

गोल्ड लोन ने बीते वर्षों में बैंकों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया है। इससे लोन पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ ही ब्याज आय में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, गोल्ड लोन के बढ़ते पोर्टफोलियो से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत कुल ऋण में कम हुआ है। गोल्ड लोन एक सुरक्षित ऋण है, जो 18 से 24 कैरेट सोने के बदले दिया जाता है। इसमें सोने के आभूषणों को गिरवी रखा जाता है। जब तक ऋण की पूरी राशि नहीं चुकायी जाती, तब तक बैंक सोने के आभूषणों को मुक्त नहीं करता।

आम तौर पर यह ऋण चुकौती एकमुश्त की जाती है। अप्रैल, 2026 से गोल्ड लोन को और सुरक्षित बनाने के लिए ऋण राशि के आधार पर नया लोन टू वैल्यू (एलटीवी)



तय किया जायेगा। उदाहरण के लिए, 2.5 लाख रुपये तक एलटीवी 85 होगा, यानी मार्जिन 15 प्रतिशत। वहीं, 2.5 से पांच लाख रुपये तक एलटीवी 80 प्रतिशत रहेगा और पांच लाख से ऊपर यह 75 प्रतिशत होगा। ऋण राशि को एलटीवी से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि यदि सोने की कीमत गिरती है, तो एलटीवी इसे कवर कर सके और बैंक को नुकसान न हो।

हाल के वर्षों में करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक जैसे बैंकों में गोल्ड लोन का हिस्सा काफी बढ़ गया है। आज इन बैंकों के कुल कर्जे में से एक बड़ा हिस्सा केवल गोल्ड लोन से जुड़ा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में दिये बयान के अनुसार, मई, 2025 तक गोल्ड लोन की कुल राशि बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जो मई, 2024 में 1.16 लाख करोड़ रुपये थी।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर, 2025 तक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 15.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, क्योंकि इसकी कीमत में वृद्धि ने बैंकों को इस सुरक्षित क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। नवंबर, 2025 में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 42 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी। इन्वेस्टमेंट इनफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (इक्रा) ने भी अनुमान लगाया है कि मार्च, 2026 तक संगठित गोल्ड लोन बाजार 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। सोने की कीमत में वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक की असुरक्षित ऋणों पर सख्ती के कारण गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष गोल्ड लोन का वितरण 91 प्रतिशत तक बढ़ गया है। वर्ष 2026 की शुरुआत में सोने की कीमतें बढ़ीं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद मुनाफावसूली और वैश्विक घटनाओं के कारण इसमें गिरावट आयी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि 2025 में मजबूत वृद्धि के बाद, 2026 में सोने का रिटर्न मध्यम हो सकता है। हालांकि, अनिश्चितता के कारण इसकी कीमत उच्च स्तर पर स्थिर रह सकती है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 के अंत तक सोने की कीमत लगभग 5,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है, जिससे भारत में इसकी कीमत 1.7 लाख से 1.9 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है।

प्रदेश के कई जिलों में बनेंगी 15 फोरलेन सड़कें



■ 90.5 किमी मार्ग के लिए 708 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। प्रदेशवासियों को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपये मंजूर किए हैं। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस राशि से विभिन्न जिलों में कुल 90.5 किमी फोरलेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इनके निर्माण से प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात और जॉम से मुक्ति के साथ ही यात्रा का समय घटेगा। फोरलेन सड़कों से सुरक्षित यातायात के साथ ही आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इससे कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में दुर्ग-धमधा-बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक 0.5 किमी फोरलेन मार्ग के लिए तीन करोड़ 41 लाख रुपए, स्मृति नगर पेट्रोल पंप से आई.आई.टी. जेवरा सिरसा तक 7 किमी फोरलेन सड़क के लिए 20 करोड़ 64 लाख रुपये, मिनी माता चौक से महाराजा चौक-ठगड़ा बांध तक 4.70 किमी फोरलेन मार्ग के लिए 28 करोड़ 58 लाख रुपये तथा महाराजा चौक से बोरसी चौक तक 1.80 किमी फोरलेन सड़क के लिए 23 करोड़ 97 लाख रुपये मंजूर किए हैं।विभाग ने रायगढ़ में ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक तक 2.50 किमी के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 41 करोड़ 49 लाख रुपये, रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 55 करोड़ 29 लाख रुपये, रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के किमी 1 से किमी 5 तक विद्युतीकरण सहित फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 81 करोड़ 48 लाख रुपये और 6 किमी तमनार फोरलेन बायपास के निर्माण के लिए 152 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

रायपुर जिले में अभनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 2.8 किमी लंबाई के फोरलेन में उन्नयन के लिए 17 करोड़ 9 लाख रुपये, राजिम में नवीन मेला स्थल से लक्ष्मण झूला तक 3.50 किमी फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 34 करोड़ 20 लाख रुपये, अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी लंबाई के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए 61 करोड़ 34 लाख रुपये, बिलासपुर में 13.40 किमी कोनी-मोपका फोरलेन बायपास मार्ग के लिए 82 करोड़ 80 लाख 26 हजार रुपये और कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग में 21 किमी सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 71 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में कुल 7.30 किमी लंबाई के तीन सड़कों के फोरलेन में उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 85 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इनमें 2 किमी लंबा पत्थलगांव के इंदिरा चौक से जशपुर रोड, 1.50 किमी लंबा इंदिरा चौक से अंबिकापुर रोड तथा 3.80 किमी लंबा इंदिरा चौक से रायगढ़ रोड शामिल हैं। विभाग ने कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के किमी 50 से किमी 57 तक फोरलेन में उन्नयन और डिवाइडर निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 21 लाख रुपये मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। फोरलेन सड़कों का विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार भी तैयार करता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास में बड़े पैमाने पर निवेश कर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मनरेगा में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग

ई-केवायसी, जियो-टैगिंग और क्यूआर कोड से पारदर्शिता को मिली नई गति



रायपुर। मनरेगा में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, ई-केवायसी, जियो-टैगिंग और क्यूआर कोड से पारदर्शिता को मिली नई गतिरायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने विभिन्न प्रमुख मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। 97त्न सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूर्ण 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में राज्य ने 97 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवायसी पूर्ण कर लिया है, जिससे भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है। जिसके तहत प्रदेश के 58.16 लाख श्रमिकों का ई-केवायसी तथा 11.32 लाख निर्मित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हुई है। 11,668 ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से 11,668 ग्राम पंचायतों में 2,86,975 कार्यों की जीआईएस आधारित कार्ययोजना तैयार की गई है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक योजना निर्माण सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही मनरेगा कार्यस्थलों पर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित एनएमएमएस प्रणाली के उपयोग से उपस्थिति की निगरानी अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है।

क्यूआर कोड से आमजन को सीधी जानकारी ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से नागरिक, कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक सितंबर से अब तक लगभग 5 लाख से अधिक स्कैन दर्ज किए गए हैं। जिससे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण एवं योजनाओं की जमीनी समीक्षा की जाती है।

फार्मेसी शिक्षा और शोध से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था : जायसवाल



रायपुर। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के अवसर पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित फार्मा अन्वेषण 2026 कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम की थीम भविष्य का फार्मा इकोसिस्टम- अकादमिक जगत, उद्योग, अनुसंधान, नियामक और व्यवहार के बीच समन्वय रही, जिसमें फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग के बेहतर तालमेल पर विशेष चर्चा की गई।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि फार्मेसी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था में इसकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ फार्मेसी शिक्षा और रिसर्च को भी प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने युवाओं और शोधार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से ही हम बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अकादमिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे नए अवसरों का सृजन हो सके।

कार्यक्रम में कीनोट सेशन, इंडस्ट्री-एकेडमिक संवाद, पेटेंट एवं इनोवेशन शोकेस, ओरल एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन जैसे विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें छात्रों, शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस आयोजन के माध्यम से फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी वितरण तय मापदंड और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत



रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरण तय मापदंड और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन जहां भी गड़बड़ी मिली है, वहां सुधार किया जा रहा है और जरूरत पडने पर साडियां बदली जाएंगी।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी गई साडियों की लंबाई और गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक्शन लिया है। विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार के प्रावधान के तहत हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को साल में दो साड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके लिए प्रति साड़ी 500 रुपए तय हैं। इसी आधार पर राज्य में करीब 1.94 लाख साडियों की आपूर्ति का आदेश छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी को दिया गया था। साडियों के रंग, डिजाइन और लंबाई का मापदंड राज्य स्तर पर तय किया गया था। इसके अनुसार साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर और ब्लाउज पीस सहित कुल लंबाई 6.30 मीटर निर्धारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग को साड़ी की आपूर्ति से पहले छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़ी एजेंसी के सैंपल की जांच तकनीकी एजेंसी राइट्स लिमिटेड, मुंबई से कराई गई थी, जिसमें गुणवत्ता सही पाई गई।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को साड़ी वितरित की गई, हालांकि वितरण के बाद दुर्ग, धमतरी, रायगढ़ और कबीरधाम जिलों से कुछ शिकायतें सामने आईं।

विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को प्रभावी बनाने का लिए मंत्री ने दिए निर्देश



रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी बनाना सुनिश्चित करें। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज ग्राउंड, रायपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन आज स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपेक्षा की गई कि वे डॉ. भीमराव अंबेडकर के समान समता, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दें तथा राज्य के शिक्षा स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, दीप मंत्र एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर की जीवनी के उल्लेख से करते हुए उनके संघर्षों एवं नागरिकों को समान अधिकार दिलाने में दिए गए योगदान को स्मरण किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यभर के लगभग 751 विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुखी बनाना रहा। बैठक में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारण, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी एवं सफलता बढ़ाने की रणनीति, पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया, अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार, पीटीए बैठकों की समीक्षा तथा पालक-अधिकारियों की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

तीनों चुनावी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी: दीपक बैज



रायपुर। असम, केरल और पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में प्रचंड बहुमत का दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आम जनता का स्पष्ट रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और इन तीनों राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार को इन राज्यों की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देने का मन पहले ही बना लिया था, जनता का रुझान कांग्रेस के साथ है और परिणाम भी उसी के अनुरूप आयेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। असम की जनता उन्मादी भाषणों, धनबल और प्रशासनिक आतंक से ऊब चुकी है, असम में बदलाव के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए जनता उमड़ चुकी है। हेमंता बिसवा सरमा की बौखलाहट और अभद्र भाषा का प्रयोग इस बात का प्रमाण है। भ्रष्टाचारी तानाशाह अब बच नहीं सकते। केंद्र की सरकार, अमित शाह और निर्वाचन आयोग भी मिलकर अब असम में बदलाव को रोक नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए असम की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है।

कानून व्यवस्था बदहाल, कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं : शुक्ला

रायपुर। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की सरकार में न आम आदमी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है और न ही महिलाएं और छात्राएं सुरक्षित है। अब तो पुलिस अधिकारियों के परिजन भी सोशल मीडिया में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विगत 24 घंटे के भीतर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की दो-दो घटनाएं हुई, तेलीबांधा में एक व्यापारी को सरेआम चाकू मार दिया गया, राजधानी के ही सेजबहार में एक परिवार रात में कहीं से वापस आ रहा था, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, किसी परिचित से उन्होंने पेट्रोल लाने कहा वे लोग इंतजार कर ही रहे थे, उसी समय चार-पांच गुंडे वहां आ गए उन्होंने परिवार की महिलाओं से छेड़खानी शुरू कर दी, उनके कपड़े फाड़े गये जब परिवार के मुखिया ने विरोध किया तो उसके ऊपर डंडे और चाकू से प्रहार किया गया, परिवार भाग कर झाड़ी में छुप गए और रात भर वही छुपे रहने मजबूर रहे। गुंडे बदमाशों में कानून और प्रशासन का डर खत्म हो चुका है, भयमुक्त वातावरण देने में भाजपा की सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है।भाजपा सरकार में आम व्यक्ति तो दूर पुलिस अधिकारियों के परिजन भी सुरक्षित नहीं है।



717 सड़क स्वीकृत किये थे, वो अब तक बना क्यो नही: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव से पूछा वित्तीय वर्ष 2025 में जो 717 सड़क स्वीकृत होने का दावा किये थे आज एक साल बाद वो सड़क बना क्यों नही है? जनता सड़क ढूंढ रही है? क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो साल में मात्र पौन किलोमीटर सड़क बनाने का कार्यादेश जारी हुआ था। सरकार की सड़क निर्माण को लेकर विफलता सामने आने के बाद आपके द्वारा 717 सड़क का दावा कर नाकामी छिपाने का प्रयास किया गया है।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल में सड़क निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत कार्य हो नहीं रहा है, जनता गड्ढों एवं खस्ताहाल सड़क से परेशान है। दावा किया गया था कि दिसम्बर 2025 तक सभी खराब सड़कों को सुधार ली जायेगी। लेकिन आज भी अधिकांश सड़कों की खराब होने की शिकायत मिल रही है। नयी सड़क बनना तो दूर की बात है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव को जनता को जवाब देना चाहिये। 717 सड़कों की निर्माण की कार्यादेश एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्माणधीन सड़को सूची एवं निर्माण की स्थिति के बारे में प्रगति रिपोर्ट बताना चाहिये।



महिला एवं बाल विकास विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है: वंदना

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साहिकाओं को गुणवत्ताहीन, छोटी एवं घटिया क्वालिटी के साड़ी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग तो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है। अब तो भ्रष्टाचार की हद पार हो गई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं औ सहायिकाओं को 5 मीटर से भी कम लंबाई और चौड़ाई एवं घटिया साड़ियां महिला एवं बाल विकास विभाग में वितरण किया गया है। साड़ियों के लंबाई और चौड़ाई में कम होने के कारण महिलाएं साड़ी का उपयोग नहीं कर पा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग में एक महिला मंत्री के होते हुए महिलाओं के साथ उनके अधिकार पर डाका डाला जा रहा है और महिला मंत्री कमीशन-कमीशन खेल रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में यह पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी कई भ्रष्टाचार सामने आए हैं जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में 40 करोड़ से अधिक की पोषण सामग्री खरीद में अनियमितता, सामूहिक कन्या विवाह योजना में बिना टेंडर वर्क आर्डर और प्रदेश के लगभग 2899 आंगनबाड़ी केंद्रों में 16 करोड़ की लागत से टीवी और आरओ यूनिट की खरीद में नियमों



योजनाओं के लाभ से वंचित कर रही है सरकार: वर्मा

रायपुर। तमाम सरकारी योजनाओं में बार बार वेरिफिकेशन और ई केवाईसी के लिए बाध्य करके लाइन लगवाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ से वंचित कर रही है। तरह तरह के बहाने तलाशे जा रहे हैं। जो लोग चुनाव के समय पात्र थे वो भाजपा के चुनाव जीतने के बाद अपात्र कैसे हो गए? किसान सम्मान निधि, कृषि मजदूर कल्याण योजना, महतारी वंदन योजना, पीडीएस सहित सभी योजनाओं में लगभग यही हाल है। विगत दो साल में भाजपा की सरकार आने के बाद से तीन-तीन बार राशन कार्ड का नवीनीकरण किया गया, मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री की फोटो लगवाने के लिए सभी पुराने राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। आधार कार्ड मांगे गए तब भी केवाईसी का बहाना बताया गया, वन नेशन वन कार्ड के नाम पर फिर से लाइन लगवाए, अब एक बार फिर से केवाईसी का बहाना कर बड़ी संख्या में राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महतारी वंदन योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ के लगभग सवा करोड़ विवाहित महिलाओं से फार्म भरवायें, योजना जब शुरू हुई।



मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी के क्रियान्वन की समीक्षा की

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में काम हो: विकासशील



रायपुर। विकासशील ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभाग के अंतर्गत ऐसी सभी सेवाएं जो सीधे जनता से जुड़ी है, उन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की जाये तथा अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाईन किया जाये। समय सीमा में सेवाओं का लाभ हितग्राही को दिया जाए। समय सीमा में सेवाएं यदि नहीं दी जाती हैं तो संबधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिव की बैठक लेकर विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभागीय सेवाओं के क्रियान्वन समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता से जुड़ी सभी शासकीय सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना हैं। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के कहा कि वे अपने विभाग के अंतर्गत और सेवाएं जो अधिनियम के अंतर्गत लायी जा सकती है, उन्हे चिन्हित कर अधिसूचित करना सुनिश्चित करें और सुशासन एवं अभिसरण विभाग को इसकी सूची उपलब्ध कराएं। बैठक में बताया गया की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा की प्रभावी क्रियान्वन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही हैं। मुख्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियो को विभागीय सेवओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने के लिए मार्ग दर्शन दिया। भगत ने बताया की छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष में प्रदाय की जा रहीं समानान्तर सेवाओं एवं संबंधित विभागों की सेवाओं की सांकेतिक रूप से मैपिंग की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की और सेवाओं को चिन्हित कर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने प्रस्तावित करें। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार उपस्थित थे।

आधारभूत जीवन के लिए कॉमन्स महत्वपूर्ण



रायपुर। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि साझा प्राकृतिक संसाधनों (कॉमन्स) पर जनजातिय समुदायों के अटूट विश्वास उनके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल जंगल, जमीन, संस्कृति और पर्यावरण, विरासत संरक्षण एवं संवर्धन में कॉमन्स की प्रभावी भूमिका है। उन्होंने न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की बात करें तो स्थानीय लोग नीति-कार्यान्वयन में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलाव के लिए सरकार एक समर्पित टास्क फोर्स बनाने की प्रक्रिया में है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य पूरे राज्य में अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के मध्य संतुलित समन्वय सुनिश्चित करना है।

कॉमन्स सम्मेलन संवाद में सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोणों को केंद्र में रखा गया था, जिसकी शुरुआत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री जागेश्वर यादव और श्री पांडी राम मंडावी तथा गौर मारिया नृत्य कलाकार सुश्री लक्ष्मी सोरी जैसे सम्मानित अतिथियों के प्रारंभिक उद्बोधनों से हुई। कॉमन्स के सुशासन और सामुदायिक संरक्षण पर केंद्रित दो दिवसीय छत्तीसगढ़ कॉमन्स कंवीनिंग का शुभारंभ आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने किया। कार्यशाला नवा रायपुर ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेक्टर-24, में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स पहल के अंतर्गत विभिन्न साझेदार संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.